



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 05 अक्टूबर, 2021 / 13 आश्विन, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 23 सितम्बर, 2021

संख्या: टी0पी0टी0-ई(3)-32/2018-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 212 की उप-धारा(1) के साथ पठित धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 5-24/88-टी0पी0टी0-III तारीख

12 जुलाई, 1999 द्वारा राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 27 जुलाई, 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और उन्हें जन साधारण की सूचना के लिए राजपत्र(ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है;

इन प्रारूप नियमों द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति को यदि इन नियमों की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह/वे लिखित में आक्षेप (आक्षेपों) या सुझाव(सुझावों) को उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र(ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा/सकेंगे।

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो/हों पर उक्त प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात:-

### प्रारूप नियम

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान (तृतीय संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. मूल नियमों के राजभाषा पाठ के नियम 214 का प्रतिस्थापन.**—हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 214 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

**"214. प्रतिकर के दावे के लिए आवेदन.**—(1) प्रतिकर के दावे के लिए प्रत्येक आवेदन धारा 166 के अधीन प्रारूप एच.पी.एम.ए.सी.टी.(अ) में अतिरिक्त प्रतियों के साथ (दावा आवेदन में वर्णित प्रत्यर्थियों की संख्या के समान) किया जाएगा।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होगा:-

(क) समस्त दस्तावेज जिन पर आवेदक अपने दावे के संदर्भ में निर्भर है; दस्तावेजों की समुचित रूप से तैयार की गई सूची में प्रविष्ट हैं, परन्तु जब तक दावा अधिकरण का यह समाधान नहीं हो जाता कि आवेदक को अच्छे और पर्याप्त कारण से ऐसे दस्तावेज को पूर्वतर दायर करने से रोका गया था, तब तक वह उसके दावे के समर्थन में आवेदन के साथ संलग्न नहीं किए गए किसी दस्तावेज पर निर्भर होने के लिए अनुज्ञात न कर सकेगा;

(ख) जब तक दावा अभिकरण द्वारा कारणों को लिखित में अभिलिखित कर ऐसा करने से छूट प्रदान न की जाए, तब तक दावा अभिकरण के समाधानप्रद रूप में आवेदक(कों) की पहचान के सबूत;

(ग) अधिवक्ता या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित आवेदक(कों) के पासपोर्ट साइज फोटो;

(घ) अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट और यदि ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है तो उनके कारण; और

(ङ) चोटों का चिकित्सा प्रमाण-पत्र या उनका प्रभाव.—

(3) दावा अधिकरण अपने इस समाधान के लिए कि कोई मिथ्या या दुस्संधिपूर्ण दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है, आवेदक से निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा:-

(क) समस्त पूर्ववर्ती दुर्घटनाएं जिनमें, यथास्थिति, आवेदक या मृत व्यक्ति शामिल रहा है, का पूर्ण विवरण;

(ख) ऐसी पूर्ववर्ती दुर्घटनाओं में संदत्त प्रतिकर की रकम, पीड़ित व्यक्ति और उस व्यक्ति, जिसने संदत्त भुगतान का संदाय किया है, का नाम और विवरण; और

(ग) खण्ड (ख) में वर्णित व्यक्तियों, यदि कोई हो, के आवेदक के साथ सम्बन्ध ।

(4) कोई आवेदन, जो जांच पर त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, को दावा अधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि, किन्तु जो दो सप्ताह से अनधिक नहीं होगी, के भीतर त्रुटियों को दूर करने के पश्चात् पुनः प्रस्तुतीकरण हेतु वापस किया जा सकेगा।

(5) प्रतिकर के लिए प्रत्येक आवेदन विहित रजिस्टर में पृथक्: रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा ।”।

**3. नियम 214—क से 214—च का अन्तः स्थापन.—**उक्त नियमों के नियम 214 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

**“214—क मोटर दुर्घटना मामलों में अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी के कर्तव्य.—**(1) अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अन्वेषण करते समय निम्नलिखित सहित यथा संभवशीघ्रता से आधुनिक तकनीक का प्रयोग करेगा.—

(क) दुर्घटना स्थल पर घेरा बनवाना और फिर स्थल का ऐसे कोणों से छायाचित्र लेना जिससे वह स्पष्ट दिखे और यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है तो यथास्थिति, सड़कों या स्थल का दुर्घटनाग्रस्त यान (यानों) या व्यक्ति (व्यक्तियों) की स्थिति, अभिन्यास और चौड़ाई आदि उपदर्शित करते हुए स्थल प्लान तैयार करना, मापमान तैयार करना और ऐसे अन्य तथ्य, जो कि इस संबन्ध में साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और दावा अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए सुसंगत हो सकेंगे, को संरक्षित करना;

(ख) दुर्घटनाग्रस्त मोटर यान से संबंधित बीमा प्रमाण पत्र/पॉलिसी के पूरे विवरण एकत्रित करना और अधिनियम की धारा 158 की उप-धारा(1) में उल्लिखित दस्तावेजों को पेश किए जाने की अपेक्षा करना और तदुपरि या तो रसीद देकर उनको अपने आधिपत्य में रखना या उनकी सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित प्रतियां अपने पास रखना;

(ग) खण्ड (ख) में उल्लिखित दस्तावेजों की, उनको जारी करने के लिए तात्पर्यित कार्यालय/प्राधिकारी से लिखित में पुष्टि प्राप्त करके वास्तविकता सत्यापित करना;

(घ) एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(बी) में आदेश की प्राप्ति के तीस दिन से अपश्चात् अपेक्षित समस्त दस्तावेजों जिनमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्याक 2) की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट की प्रति भी है, चिकित्सा विधिक प्रमाण-पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (मृत्यु होने की दशा में), प्रथम सूचना रिपोर्ट, फोटोग्राफस, स्थल योजना, खण्ड(ग) में उल्लिखित दस्तावेजों की छायाप्रतियां, उनकी वास्तविकता के प्रमाणन से संबंधित रिपोर्ट यदि प्राप्त हुई हों, या अन्यथा की गई कार्रवाई सहित एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(डी) के भाग-I में दावा अधिकरणों को दुर्घटना से सम्बन्धित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ङ) व्यक्ति, जो प्रतिकर के लिए आवेदन देने की वांछा रखता है और जो किसी दुर्घटना में अंतर्वर्लित है या, यथास्थिति, उसका निकटतम संबंधी या मृतक का विधिक प्रतिनिधि या बीमा कंपनी द्वारा एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(सी) में आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को तीस दिनों के भीतर एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(डी) के भाग-I में दुर्घटना से सम्बन्धित समस्त सूचना और विशिष्टियां प्रदान करना :

परंतु बीमा कंपनी को ऐसी सूचना दस रुपए प्रति पृष्ठ फीस संदाय करने पर प्रदान की जाएगी।

(2) उप नियम (1) के उपबंध हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन दिए गए कर्तव्यों के रूप में समझे जाएंगे और इनका कोई भी भंग उक्त अधिनियम में परिकल्पित परिणामों को अपरितार्थ करेगा।

**214—ख मोटर दुर्घटना दावों की जांच.**—किन्हीं अन्य प्रवृत्त नियमों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी मोटर दुर्घटना दावों की जांच पुलिस द्वारा निम्नलिखित रीति में की जाएगी,—

- (1) मोटर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल का दौरा करेगा, स्थल का निरीक्षण करेगा, सभी कोणों से स्थल के फोटो लेगा, यथास्थिति, सड़क या स्थान का अभिन्यास, यथास्थिति, यान या व्यक्ति की अवस्थिति, ऐसे अन्य तथ्य जो सुसंगत हो सकेंगे, को अभिदर्शित करके अनुमाप के अनुसार नक्शा तैयार करेगा और दुर्घटना से सम्बन्धित समस्त साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के आशय से प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का भी परीक्षण करेगा।
- (2) अन्वेषण(जांचकर्ता) पुलिस अधिकारी निम्नलिखित सम्पूर्ण विशिष्टियों और दस्तावेजों को एकत्रित करेगा,—
  - (i) दुर्घटना की तारीख, समय और स्थान;
  - (ii) दुर्घटना में घायल या मृत व्यक्ति के विवरण;
  - (iii) उल्लंघन करने वाले यान के चालक का नाम और पता;
  - (iv) उल्लंघन करने वाले यान के चालक की चालन अनुज्ञप्ति;
  - (v) उल्लंघन करने वाले यान के स्वामी का नाम और पता;
  - (vi) उल्लंघन करने वाले यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र;
  - (vii) उल्लंघन करने वाले यान की बीमा पॉलिसी या वैकल्पिक कवर नोट या बीमा प्रमाण—पत्र;
  - (viii) उपयुक्तता प्रमाण—पत्र और अनुज्ञा पत्र (यदि वाणिज्यिक यान है);
  - (ix) दुर्घटना के साक्षियों के नाम और पते;
  - (x) दुर्घटना के घटने की परिस्थितियां;
  - (xi) आहत व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में,—
    - (क) मृतक की आयु का प्रमाण(सबूत);
    - (ख) मृत्यु प्राण प्रमाण—पत्र;
    - (ग) पोस्टमार्टम रिपोर्ट;
    - (घ) मृतक की आय का सबूत;
    - (ङ) आश्रितों के ब्यौरे (उनकी आय, व्यवसाय और वैवाहिक प्रास्थिति); और

(च) उपचार पर व्यय; और

(xii) आहत व्यक्ति को किसी चोट की दशा में;

(क) चिकित्सा विधिक प्रमाण पत्र;

(ख) घायल की आयु का सबूत;

(ग) घायल की आय का सबूत;

(घ) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को आई चोट का स्वरूप;

(ङ) घायल द्वारा लिया गया उपचार (अस्पताल से छुट्टी के सारांश सहित);

(च) अक्षमता प्रमाण पत्र (यदि सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किया गया है);

(छ) उपचार, प्रवहण, विशेष आहार या परिचर आदि पर व्यय; और

(ज) कार्य से अनुपस्थिति का सबूत (जिसके आधार पर चोट के कारण आय की क्षति निर्धारित की जानी है या दावा किया गया है) जैसे नियोक्ता से प्रमाण पत्र और हाजिरी रजिस्टर से उद्धरण या यात्रा दैनिकी अभिलेख या सदृश अभिलेख।

(3) अन्वेषण पुलिस अधिकारी ऐसे दस्तावेज जारी करने के लिए तात्पर्यित कार्यालय या प्राधिकारी या व्यक्ति से लिखित में पुष्टी अभिप्राप्त करके एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(डी) के भाग-II में उल्लिखित दस्तावेजों की अधिप्रमाणिता सत्यापित करेगा या प्राधिकारी से प्रश्नगत दस्तावेजों चालक की अनुज्ञप्ति और यान के अनुज्ञापन (परमिट)(जहां लागू है) सहित किन्तु सत्यापन तक ही सीमित नहीं है की अधिप्रमाणिता के किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, ऐसी उत्तरभावी जांच या सत्यापन, जो भी आवश्यक है, करेगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, अन्वेषण अधिकारी द्वारा आवेदन दिए जाने के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर उल्लंघनकर्ता यान की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, चालन अनुज्ञप्ति उपयुक्तता और परमिट का सत्यापन करेगा। सम्बद्ध अस्पताल दुर्घटना से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अन्वेषण अधिकारी को चिकित्सा-विधिक प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करेंगे।

(5) अन्वेषण पुलिस अधिकारी उप नियम (3) और (4) में विनिर्दिष्ट उपरोक्त दस्तावेजों का संग्रहण करने और उनके सत्यापन की तारीख की प्रक्रिया को पूरा करेगा और दुर्घटना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आपराधिक मामले की जांच को पूरा करेगा। अन्वेषण अधिकारी दुर्घटना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर दावा अधिकरण के समक्ष एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(घ) में दुर्घटना सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। दुर्घटना सूचना रिपोर्ट अपेक्षित दस्तावेजों, (जिनमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट की प्रति, पुलिस के समक्ष की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, चिकित्सा विधिक प्रमाण पत्र, मृत्यु की दशा में पोस्टमार्टम रिपोर्ट) फोटोग्राफ, स्थल का नक्शा, यांत्रिक जांच रिपोर्ट, अभिग्रहण मेमो(नोट), और एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(घ) के भाग-II में उल्लिखित दस्तावेज और उनकी प्रमाणिकता की पुष्टिकरण से संबंधित रिपोर्ट यदि प्राप्त हुई है या अन्यथा की गई कार्रवाई सहित संलग्न होगी। दुर्घटना सूचना रिपोर्ट की प्रति समसामयिक बीमा कंपनी, पीड़ित या दुर्घटना में उनके दावेदारों और उल्लंघनकर्ता यान के स्वामी या चालक को भी भेजी जाएगी।

(6) दुर्घटना सूचना रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने पर बीमा कम्पनी दस दिन की अवधि के भीतर पदाभिहित अधिकारी नियुक्त करेगी। पदाभिहित अधिकारी मामले के निपटान या प्रक्रमण और उसकी नियुक्ति की तारीख के बीस दिन की अवधि के भीतर संदाय की जाने वाली रकम के बारे में विधि के अनुसार लिखित में तर्कसंगत निर्णय पारित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) यदि अन्वेषण पुलिस अधिकारी अपने नियंत्रण से परे के कारणों से तीस दिन की अवधि के भीतर मामलों जैसे हिट एंड रन दुर्घटनाओं के मामले, ऐसे मामले जहां पक्षकार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहते हैं या जहां पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं और उसका उपचार चल रहा है, की जांच पूरी करने में असमर्थ है तो जांच अधिकारी समय के विस्तार के लिए दावा अधिकरण से संपर्क करेगा, जिस पर दावा अधिकरण प्रत्येक मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समय का विस्तार करेगा।

(8) यदि उल्लंघन करने वाले यान का बीमा नहीं हुआ पाया जाता है, तो उल्लंघन करने वाले यान के स्वामी और चालक को अधिनियम की धारा 196 के अधीन अभियोजित किया जाएगा।

(9) यदि चालक की चालन अनुज्ञप्ति जाली पायी जाती है, तो अन्वेषण पुलिस अधिकारी चालक या ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो जालसाजी या जाली चालन अनुज्ञप्ति को जारी करने में संलिप्त हैं, को अभियोजित करेगा।

(10) अन्वेषण पुलिस अधिकारी दुर्घटना सूचना रिपोर्ट सहित चालक, स्वामी, दावेदार और प्रत्यक्षदर्शी को दावा अधिकरण के समक्ष पेश करेगा। तथापि, यदि पुलिस अपने नियंत्रण से परे कारणों हेतु सुनवाई की पहली तारीख को दावा अधिकरण के समक्ष स्वामी, चालक, दावेदार और प्रत्यक्षदर्शी को पेश करने में असमर्थ है तो दावा अधिकरण उन्हें पेश होने के लिए तीस दिन के अपश्चात् की अवधि की तारीख हेतु अन्वेषण पुलिस अधिकारी के माध्यम से तामील किया जाने वाला नोटिस जारी करेगा। अन्वेषण पुलिस अधिकारी, संबंधित बीमा कंपनी को दावा अधिकरण के समक्ष दुर्घटना सूचना रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख के बारे में एक अग्रिम सूचना देगा ताकि बीमा कंपनी के लिए नामित अधिवक्ता दावा अधिकरण के समक्ष सुनवाई की तारीख को उपस्थित रह सके।

(11) दावा अधिकरण इस बात की जांच करेगा कि क्या दुर्घटना सूचना रिपोर्ट सभी तरह से पूर्ण है और इस संबंध में उचित आदेश पारित करेगा। यदि दुर्घटना सूचना रिपोर्ट पूर्ण नहीं है, तो दावा अधिकरण अन्वेषण पुलिस अधिकारी को उक्त रिपोर्ट को पूर्ण करने का निर्देश देगा और इसके पूर्ण करने की तारीख नियत करेगा।

(12) दावा अधिकरण अन्वेषण अधिकारी द्वारा दायर की गई दुर्घटना सूचना रिपोर्ट को अधिनियम की धारा 166(4) के अधीन दावा याचिका के रूप में लेगा। तथापि यदि पुलिस सुनवाई की पहली तारीख को दावेदारों को पेश करने में असमर्थ है, तो दावा अधिकरण आरंभ में दुर्घटना सूचना रिपोर्ट को एक विविध आवेदन के रूप में रजिस्टर करेगा, जिसे दावेदारों की उपस्थिति के पश्चात् दावा याचिका के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(13) दावा अधिकरण बीमा कंपनी को दुर्घटना सूचना रिपोर्ट की जांच करने के लिए और विधि के अनुसार दावेदारों को संदेय प्रतिकर(मुआवजे) की मात्रा के बारे में निर्णय लेने के लिए तीस दिन का समय प्रदान करेगा। बीमा कंपनी के पदाभिहित अधिकारी द्वारा लिखित रूप में निर्णय लिया जाएगा और यह एक युक्तियुक्त निर्णय होगा। बीमा कंपनी का पदाभिहित अधिकारी अन्वेषण अधिकारी से दुर्घटना सूचना रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने की तारीख से उप नियम (6) में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दावा अधिकरण के समक्ष लिखित युक्तियुक्त निर्णय रखेगा।

(14) बीमा कंपनी के पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर, दावेदारों के लिए एक विधिक प्रस्ताव संस्थापित होगा और यदि उक्त राशि दावेदारों के लिए उचित और स्वीकार्य है, तो दावा अधिकरण एक सहमति अधिनिर्णय पारित करेगा और बीमा कंपनी को इस प्रकार प्रदान की गई राशि का भुगतान करने के लिए तीस दिन का समय देगा। तथापि सहमति अधिनिर्णय पारित करने से पूर्व, दावा अधिकरण, यह सुनिश्चित करेगा कि दावेदारों को विधि के अनुसार उचित प्रतिकर प्रदान किया जाए। दावा अधिकरण दावेदारों के हिस्सों और संवितरण की रीति के संबंध में एक आदेश भी पारित करेगा।

(15) यदि दावेदार बीमा कंपनी के प्रस्ताव का तुरंत उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं तो दावा अधिकरण उन्हें उक्त प्रस्ताव का उत्तर देने के लिए तीस दिन अपश्चात् का समय देगा।

(16) यदि बीमा कंपनी का प्रस्ताव दावेदारों को उचित और स्वीकार्य नहीं है या यदि बीमा कंपनी के पास विधि के अधीन उसके पास कोई प्रतिवाद उपलब्ध है, तो दावा अधिकरण अधिनियम की धारा 168 और 169 के अधीन जांच करने हेतु कार्यवाही करेगा और तत्पश्चात् तीस दिन की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित करेगा।

(17) दुर्घटनाग्रस्त मोटर यान के निस्तार के विरुद्ध प्रतिषेध,—

(क) कोई भी न्यायालय किसी दुर्घटनाग्रस्त मोटर यान का निस्तार नहीं करेगा जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या शारीरिक चोट या संपत्ति को क्षति हुई हो, यदि ऐसा यान रजिस्ट्रीकृत स्वामी के नाम पर लिए गए तीसरे पक्ष के जोखिमों के विरुद्ध बीमा की पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता है, या यदि रजिस्ट्रीकृत स्वामी अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने के बावजूद ऐसी बीमा पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहता है और जब तक रजिस्ट्रीकृत स्वामी प्रतिकर, जो इस तरह की दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले दावे के मामले में प्रदान किया जा सकेगा, को संदत्त करने हेतु न्यायालय के प्रमाणीकरण के लिए पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं कर देता है।

(ख) यदि मोटर यान तीसरे पक्षकार जोखिम के विरुद्ध बीमा की पॉलिसी के अन्तर्गत नहीं आता है या जब मोटर यान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी उप नियम(1) में उल्लिखित परिस्थितियों में ऐसी पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा वाहन को अपने कब्जे में लेने के तीन मास की समाप्ति पर, उस क्षेत्र जहां दुर्घटना हुई है, पर अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा मोटर यान को और उसके विक्रय आगामों को प्रश्नगत क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले दावा अधिकरण के उत्पन्न दावा मामले में अधिनिर्णित किया गया है या अधिनिर्णित किया जा सकेगा:

परन्तु जहां दुर्घटना में शामिल यान का निर्गमन प्रमाण पत्र उपलब्ध है और उक्त यान के चालक के पास विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है तो अन्वेषण पुलिस अधिकारी अपने स्तर पर सुपरदारी पर यान को निस्तार करेगा।

(18) पुलिस कर्मियों द्वारा कर्तव्य में किसी भी उल्लंघन के नियम 215—क के उप-नियम(2) में यथा उपबन्धित के अनुसार निपटाया जाएगा।

**214—ग रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के कर्तव्य.**—संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि,—

(क) एच.पी. प्ररूप—52 एम.ए.सी.टी.(एफ) में आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर दुर्घटना में शामिल मोटर यान या ऐसे यान के चालक की अनुज्ञप्ति के बारे में दावा अधिकरण को एच.पी. प्ररूप—52 एम.ए.सी.टी.(ई) में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें; और

(ख) किसी व्यक्ति, जो प्रतिकर के लिए आवेदन करने की वांछा रखता है या यथास्थिति उसके निकटतम सम्बन्धी या मृतक के प्रतिनिधि या बीमा कंपनी के उपयोग के कारण किसी दुर्घटना में शामिल है, से एच.पी. प्ररूप—52 एम.ए.सी.टी.(जी) में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर एच.पी. प्ररूप—52 एम.ए.सी.टी.(ई) में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करेगा:

परन्तु सूचना बीमा कंपनी को दस रुपए प्रति पृष्ठ के संदाय पर दी जाएगी

**214—घ बीमा कंपनी के कर्तव्य.**—दुर्घटना के बारे में सूचना प्राप्त होने के पश्चात् या नियम 218 के अधीन दावा अधिकरण से नोटिस प्राप्त होने पर बीमा कंपनी के मंडल प्रबंधक का यह कर्तव्य होगा कि,—

(क) दुर्घटना के बारे में सम्पूर्ण सूचना शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने के लिए अन्वेषण पुलिस अधिकारी को विहीत शुल्क के साथ एच.पी. प्ररूप—52 एम.ए.सी.टी.(सी) में आवेदन करें;

- (ख) दुर्घटनाग्रस्त मोटर यान(यानों) के बीमा के बारे में तथ्यों को अभिनिश्चित और सत्यापित करना तथा दावा मामले के नोटिस प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर इसके बारे में दावा अधिकरण को सूचित करना :
- (ग) दुर्घटनाग्रस्त मोटर यान और एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(ई) में उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे मोटर यान के चालक द्वारा धारित चालन अनुज्ञप्ति के बारे में सूचना प्राप्त करने हेतु एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(जी) में संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करें:
- (घ) ऐसे मामलों में जहां एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(डी) या एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(ई) में ऐसी बीमा कंपनी द्वारा इस प्रकार बीमाकृत मोटर यान के उपयोग के परिणामस्वरूप या तो मृत्यु या स्थायी विकलांगता कारित होने की पुष्टि की सूचना प्राप्त होती है, तो अधिनियम की धारा 140 के अधीन त्रुटि न होने के दायित्व के सिद्धान्त पर देय प्रतिकर के बराबर राशि (दावा अधिकरण में लिखित कथन के साथ जमा करना।

**214-ड रिपोर्ट की बाबत उपधारणा.**—क्रमशः अन्वेषण पुलिस अधिकारी और सम्बद्ध रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(डी) और एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(ई) के भाग-I में दावा अधिकरण को भेजी गई रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु और बीमा कंपनी द्वारा नियम 215-ग के खंड(ख) के अधीन की गई पुष्टि सही माना जाएगा और औपचारिक साक्ष्य के बिना तब तक पढ़ा जाएगा जब तक कि यह प्रतिकूल साबित न हो जाए।

**214-च पुलिस रिपोर्ट और उस पर कार्रवाई.**—(1) धारा 158 की उप-धारा(6) के अधीन पुलिस रिपोर्ट एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(डी) में की जाएगी।

(2) चालन अनुज्ञप्ति, मोटर यान रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, बीमा, परमिट आदि की सत्यापन रिपोर्ट के साथ उप-नियम(1) में उल्लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने पर दावा अधिकरण इसकी जांच करेगा और ऐसी अतिरिक्त सूचना या विवरण की मांग कर सकेगा, जैसी अधिनियम की धारा 166 की उप-धारा(4) के उपबंध के अनुसार मामले के उचित निपटान के लिए आवश्यक समझा जाए।

(3) दावा अधिकरण रिपोर्ट के परीक्षण के पश्चात् दावे के मामले को दर्ज करेगा और एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(एच) में उपस्थित होने के लिए समस्त सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस जारी करेगा, जिसमें यथास्थिति दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति या, उसका विधिक प्रतिनिधि अन्तर्गस्त यान का चालक, स्वामी और बीमाकर्ता भी हो सकेगा।

(4) उप-नियम(3) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर पक्षकार दावा अधिकरण के समक्ष अपनी उपस्थिति देंगे और दावा मामला, यदि कोई हो, घोषित करेंगे, और यदि ऐसा है तो पुलिस रिपोर्ट को दावा मामले के रूप में माना जाएगा और उसे पक्षकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किए गए ऐसे दावे के मामले के साथ जोड़ दिया जाएगा।

(5) यदि पीड़ित व्यक्ति या मृतक व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि उप-नियम(4) के अधीन नोटिस के पश्चात् उपस्थित नहीं होता है तो दावा अधिकरण यह उपधारित कर सकेगा कि उक्त पक्षकार किसी प्रतिकर के दावे को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं और ऐसी उपधारणा से ये मामले को बन्द कर देंगे।

(6) जब तक पुलिस रिपोर्ट को पक्षकारों द्वारा स्वयं प्रस्तुत स्वतंत्र दावा मामले से सम्बद्ध दावा मामले के रूप में नहीं माना जाता है, तब तक दावा अधिकरण यथास्थिति पीड़ित व्यक्ति या मृतक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि, को बुलाएगा और जो नोटिस के प्रत्युत्तर में दावा अधिकरण के समक्ष प्रतिकर के बारे में तथ्यों का विवरण यदि उनके द्वारा एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(ए) में कोई दावा किया गया है, देने के लिए उपस्थित हुए हैं।

(7) यदि पक्षकारों द्वारा किए गए दावा प्रतिकर के बारे में तथ्यों का विवरण उप-नियम (6) में विनिर्दिष्ट रीति से प्रस्तुत किया जाता है, तो मामले को उसी रीति से आगे बढ़ाया जाएगा मानो कि पक्षकार प्रतिकर के लिए सीधे दावा अधिकरण के समक्ष पेश हुआ हो।



(8) यदि पक्षकारों द्वारा प्रतिकर का दावा करने के लिए कथन किया गया है, किन्तु तत्पश्चात् उपस्थिति में चूक करता है, तो उस स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश ix के उपबंध लागू होंगे:

परन्तु यदि प्रश्नगत दुर्घटना में एक से अधिक यान अन्तर्वर्लित है और ऐसे समस्त यानों से सम्बद्ध व्यक्ति प्रतिकर के लिए दावा करते हैं, तो दावा मामले के रूप में मानी गई पुलिस रिपोर्ट को उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत दावा मामला माना जाएगा और ऐसे पक्षकारों के किसी एक या अधिक पक्षकारों की अनुपस्थिति, पक्षकारों जो निरंतर उपस्थित होते रहे हैं, के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

**4. मूल नियमों के राजभाषा पाठ नियम 217 का प्रतिस्थापन.**—उक्त नियमों के नियम 218 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

**“217 संबद्ध पक्षकारों को नोटिस.**—यदि नियम 216 के अधीन दावे के लिए कोई आवेदन निरस्त नहीं किया जाता है, तो दावा अधिकरण, उसे उस व्यक्ति, जिसके विरुद्ध आवेदक अनुतोष का दावा करता है, को एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(1) में नोटिस की तारीख के साथ इसके समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रेषित करेगा और उन्हें नियम 219 के अनुसार अपना लिखित कथन दाखिल करने के लिए कह सकेगा।

परन्तु, यदि आवेदक द्वारा लिखित कथन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेज बृहत हैं तो दावा अधिकरण विरोधी पक्षकार को इसकी प्रतियां प्रेषित करने की अपेक्षा से अभिमुक्त हो सकेगा।”।

**5. नियम 219 का प्रतिस्थापन.**—उक्त नियमों के नियम 219 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

**“219. पक्षकारों की उपस्थिति और परीक्षण.**—(1) विराधी पक्षकार, पहली सुनवाई को या उससे पूर्व, या ऐसे और समय के भीतर जैसा दावा अधिकरण अनुज्ञात करे, लिखित कथन दाखिल करेगा जो दावा अधिकरण के अभिलेख का भाग हो जाएगा।

(2) विराधी पक्षकार लिखित कथन के साथ उन तथ्यों के समर्थन में समस्त दस्तावेज जिन पर वह अपने बचाव में निर्भर करता है, दाखिल करेगा और दस्तावेजों की सूची सम्यक रूप से तैयार करेगा तथा आवेदक को भी उसकी एक प्रति देगा:

परन्तु दावा अधिकरण विराधी पक्षकार को लिखित कथन के साथ फाईल नहीं किए गए किसी दस्तावेज पर उसके बचाव के समर्थन में निर्भर रहने हेतु तब तक अनुज्ञात नहीं कर सकेगा जब तक कि इसका समाधान नहीं हो जाता है कि इसे पूर्व में ऐसे दस्तावेज फाईल करने से कतिपय सही या समुचित कारणों से वंचित किया गया था।

(3) यदि विरोधी पक्षकार दावा का विरोध करता है तो दावा अधिकरण, यदि इसके द्वारा कोई लिखित कथन फाईल नहीं किया गया है, उसका दावे के हैसियत में परीक्षण करेगा और लिखित में मौखिक कथन लेगा।

(4) दावा अधिकरण विरोधी पक्षकार से निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करने की भी अपेक्षा करेगा:—

(क) पूर्वतर समस्त दुर्घटनाओं की पूर्ण विशिष्टियां जिसमें यह अन्तर्वर्लित था और जिस मामले में दावा या तो पूर्णतः या भागतः अधिनिर्णित किया गया है; और

(ख) ऐसी पूर्वतर दुर्घटनाओं में संदत्त प्रतिकर की रकम, पीड़ितों के नाम और पता तथा व्यक्ति जिसे क्षतिपूर्ति संदत्त की गई है और विरोधी पक्षकार से उसका सम्बन्ध यदि कोई हो।”।

**6. नियम 220 का प्रतिस्थापन.**—उक्त नियमों के नियम 220 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातः—

**“220 साक्षियों को समन करना.**—यदि कार्यवाही में किसी पक्षकार द्वारा साक्षियों को बुलाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो दावा अधिकरण अन्तर्वलित व्यय के संदाय पर, यदि कोई हो, ऐसे साक्षियों की उपस्थिति के लिए, जब तक मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं समझी जाती है, समन जारी कर सकेगा:

परन्तु यदि दावा अधिकरण की राय है कि पक्षकार साक्षियों का समन करने का खर्चा उठाने में असमर्थ है तो यह व्यय के ऐसे संदाय के लिए आग्रह नहीं कर सकेगा और उस दशा में उसका व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि दावेदार पूर्णतः या भागतः दावा करने में सफल रहता है तो सरकार द्वारा इस प्रकार उपगत व्यय सरकार को संदत्त किया जाना निदेशित किया जाएगा।”।

**7. नियम 222 का प्रतिस्थापन.**—उक्त नियमों के नियम 222 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थातः—

**“222 स्थानीय निरीक्षण.**—(1) दावा अधिकरण उसके समक्ष किसी भी कार्यवाही के दौरान, किसी भी समय स्थानीय निरीक्षण करने या किसी व्यक्ति, जो दावों से सुसंगत सूचना देता है, का परीक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसे स्थल, जहाँ ऐसी दुर्घटना घटित हुई है, का दौरा कर सकेगा।

(2) कार्यवाही का कोई भी पक्षकार या ऐसे पक्षकार का कोई प्रतिनिधि, स्थानीय निरीक्षण के लिए दावा अधिकरण के साथ जा सकेगा।

(3) दावा अधिकरण स्थानीय निरीक्षण करने के पश्चात् संप्रक्षिप्त किए तथ्यों के ज्ञापन में संक्षिप्त टिप्पण करेगा और ऐसा ज्ञापन कार्यवाहियों के अभिलेख का भाग होगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन ज्ञापन कार्यवाहियों के किसी भी पक्षकार, जो इसे देखने की वांछा रखता हो, को दिखाया जा सकेगा और इसकी प्रति आवेदन करने पर ऐसे किसी पक्षकार को, दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर से प्रदान की जा सकेगी।

(5) दावा अधिकरण, किसी पक्षकार के अनुरोध पर यदि इस नियम के अधीन कोई यात्रा करता है, तो वह पक्षकार से उसके और उसके कर्मचारिवृन्द द्वारा संभाव्य उपगत किए जाने वाले वास्तविक व्ययों के बराबर रकम पहले ही निक्षेप करने की अपेक्षा कर सकेगा और वह ऐसी यात्रा के सम्बन्ध में समस्त आनुषंगिक व्यय की पूर्ति हेतु पक्षकारों द्वारा केवल इस प्रकार निक्षिप्त रकम ही निकालेगा।”।

**8. नियम 224—क और 224—ख का अन्तः स्थापन.**—उक्त नियमों के राजभाषा पाठ के नियम 224 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थातः—

**“224—क. अनुपूरक सूचना और दस्तावेज अभिप्राप्त करना.**—दावा अधिकरण, पुलिस, चिकित्सा और अन्य प्राधिकारियों से जो भी अनुपूरक सूचना और दस्तावेज आवश्यक पाए जाते हैं, अभिप्राप्त करेगा और दावे पर न्यायानिर्णय करने के लिए अग्रसर होगा, चाहे पक्षकार जिन्हें नियत दिन पर उपस्थित होने का नोटिस दिया गया था, उपस्थित है या नहीं।

**224—ख. चिकित्सा परीक्षण निदेशित की शक्ति.**—दावा प्राधिकरण, यदि यह आवश्यक समझे, किसी सरकारी या नगर पालिका अस्पताल में किसी चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारियों के किसी बोर्ड को एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(जे) में चोटिल व्यक्ति का परीक्षण करने हेतु निदेश दे सकेगा और दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई ऐसे निशक्ता (विकलांगता) यदि कोई हो की मात्रा और परिमाण उपदर्शित करते हुए

प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा और ऐसे चिकित्सा अधिकारी या बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेश की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।”।

**9. मूल नियमों के राजभाषा पाठ के नियम 228 का प्रतिस्थापन.**—उक्त नियमों के नियम 228 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

**“228 विवादकों का निर्धारण.**—(1) दावा अधिकरण, विवादकों की विरचना के पश्चात् सिविल प्रक्रिया संहिता 1908(1908 का 5) के उपबन्धों के अनुसार एक दूसरे की प्रतिपरीक्षा करने के लिए दोनों पक्षकारों को अनुज्ञात करने के पश्चात् ऐसे विवादकों को विनिश्चित करने के लिए अग्रसर होगा।

(2) दावा अधिकरण को यदि मामले के न्यायसंगत विनिचय के लिए इसे यह आवश्यक प्रतीत होता है तो वह पक्षकारों को ऐसे और साक्ष्य, जैसे वह उचित समझे, देने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई और अवसर तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह दर्शाया नहीं जाता है कि ऐसा और साक्ष्य सम्यक तत्पर्यता का प्रयोग करने के बावजूद पहले नहीं दिया गया था या ऐसा साक्ष्य उस पर विश्वास करने वाले पक्षकार की जानकारी में नहीं था।”।

**10. मूल नियमों के राजभाषा पाठ के नियम 230 का प्रतिस्थापन.**—उक्त नियमों के नियम 230 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

**“230 निर्णय और प्रतिकर को अधिनिर्णीत करना.**—(1) दावा अधिकरण आदेश पारित करते समय निर्णय में विरचित प्रत्येक विवादकों के निष्कर्ष पर, ऐसे निष्कर्षों के कारणों को, संक्षिप्त रूप में अभिलिखित करेगा और बीमाकर्ता द्वारा संदत्त किए जाने या ऐसे व्यक्ति जिस पर दायित्व डाला गया है और ऐसे व्यक्ति को भी जिसको प्रतिकर बीमाकर्ता द्वारा संदत्त किया जाना है तथा ऐसे और व्यक्ति को भी जिसको प्रतिकर संदत्त किया जाएगा, को प्रतिकर की रकम विनिर्दिष्ट करके अधिनिर्णय करेगा। अधिनिर्णीत रकम का संवितरण यथासाध्य सीधे हिताधिकारी के लेखे में इलेक्ट्रॉनिक अन्तरण (आर.टी.जी.एस. या एन.ई.एफ.टी) के माध्यम से किया जाएगा।

(2) यदि प्रतिकर दो या दो से अधिक व्यक्तियों को अधिनिर्णीत किया गया है, तो दावा अधिकरण उनमें से प्रत्येक को संदेय की जाने वाली रकम को भी विनिर्दिष्ट करेगा।

(3) दायित्व का न्याय निर्णय करने और प्रतिकर अधिनिर्णीत करने की प्रक्रिया को मृत्यु की दशा में विधिक उत्तराधिकारियों को प्रतिकर के संवितरण की प्रक्रिया से पृथक किया जा सकेगा और यदि दावा अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि मृतक व्यक्ति के विधिक उत्तराधिकारियों की पहचान और अवधारण के कारण दावेदार को वास्तविक संदाय में कुछ समय लगने की सम्भावना है, तो दावा अधिकरण अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम को अपने पास जमा करने के लिए मांग कर सकेगा, और तब प्रत्येक विधिक उत्तराधिकारी को साम्यिक(सम्यापूर्ण) ढंग से प्रतिकर का संदाय संवितरण करने हेतु विधिक उत्तराधिकारी की पहचान के लिए अग्रसर हो सकेगा।

(4) दावा अधिकरण दावेदार से द्विप्रतिक में रसीद अभिप्राप्त करेगा, जिसमें से एक प्रति उस व्यक्ति को जारी की जाएगी, जो संदाय करता है, और अन्य प्रति अभिलेख में प्रतिधारित की जाएगी।”।

**11. उक्त नियमों के राजभाषा पाठ के नियम 230 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्.**—**“230—क. दावेदारों के हित को सुरक्षित करना.**—(1) यदि दावा अधिकरण के पास जमा की गई एक मुश्त राशि, विधिक निशक्ता (विकलांगता) के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय है, तो ऐसी राशि को उसकी विकलांगता के दौरान ऐसे व्यक्ति को प्रसुविधा के लिए ऐसी रीति में, जैसे कि दावा अधिकरण निदिष्ट करे, चोटिल के किसी आश्रित या मृतक के उत्तराधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति को संदत्त की जाने हेतु, जिनको दावा अधिकरण यथास्थिति, चोटिलों या मृतक के उत्तराधिकारी के कल्याण के लिए प्रदान करने के लिए उपयुक्त समझे, विनिहित, उपयोजित या अन्यथा संव्यवहृत किया जा सकेगा।

(2) जहाँ दावा अधिकरण को इस निमित्त किए गए आवेदन पर या अन्यथा दावा अधिकरण का यदि समाधान हो जाता है कि बच्चों की उनके माता-पिता द्वारा उपेक्षा के कारण या किसी आश्रित की बदली हुई परिस्थितियों के कारण अथवा किसी अन्य पर्याप्त हेतुक के दावा अधिकरण के प्रतिकर के रूप में संदत्त किसी राशि के संवितरण के किसी आदेश या ऐसी रीति जिसमें किसी ऐसे आश्रित को संदेय किसी राशि का विनिधान या उपयोग किया जाता है या उसे अन्यथा संव्यवहृत किया जाता है, में कोई भिन्नता होती है तो दावा अधिकरण पूर्ववर्ती आदेश की भिन्नता के लिए ऐसे आगामी आदेश कर सकेगा जो यह मामले की परिस्थितियों में न्यायोचित समझे।

(3) दावा अधिकरण किसी अवयस्क के मामले में आदेश करेगा कि ऐसे अवयस्क को प्रदान किए गए प्रतिकर की रकम तब तक नियत निक्षेपों में विनिहित की जाएगी जब तक ऐसा अवयस्क व्यस्क नहीं हो जाता है। संरक्षक द्वारा या उसके किसी वाद मित्र द्वारा उपगत व्ययों को ऐसे निक्षेपों से उन्हें जमा किए जाने से पूर्व ऐसे संरक्षक या उसके ऐसे वाद मित्र द्वारा आहरित किया जा सकेगा।

(4) दावा अधिकरण, अशिक्षित दावेदारों के मामले में, आदेश देगा कि अधिनिर्णित किए गए प्रतिकर की रकम तीन वर्ष को न्यूनतम अवधि के लिए नियत निक्षेपों में विनिहित की जाए किन्तु यदि, दावेदार की आय में अभिवृद्धि करने के लिए किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति के क्रय के लिए कोई रकम अपेक्षित है तो दावा अधिकरण, समाधान होने के पश्चात् कि यह रकम वस्तुतः उसी प्रयोजन के लिए खर्च की जाएगी, ऐसे अनुरोध पर विचार कर सकेगा।

(5) दावा अधिकरण, अल्प-शिक्षित व्यक्ति की दशा में, उप-नियम (4) में दी गई अधिनिर्णित रकम के निक्षेप के लिए प्रक्रिया का तब तक चयन नहीं करेगा, जब तक कारणों को लिखित में अभिलिखित करके उसका समाधान नहीं हो जाता है कि रकम का पूर्ण या आंशिक भाग किसी विद्यमान कारबार के विस्तारण हेतु या उपनियम 4 में यथा विनिर्दिष्ट कुछ सम्पत्ति, जिस मामले में दावा अधिकरण यह, सुनिश्चित करेगा कि रकम, उस प्रयोजन, जिसके लिए वह मांगी गई थी, के लिए ही विनिहित की गई है, के क्रय हेतु अपेक्षित है।

(6) दावा अधिकरण, शिक्षित व्यक्ति की दशा में उप-नियम (4) और (5) में विनिर्दिष्ट अधिनिर्णित रकम के निक्षेप हेतु प्रक्रिया का भी चयन कर सकेगा, यदि दावेदार की आयु, वित्तीय पृष्ठ भूमि आदि अधिनिर्णित प्रतिकर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत आवश्यक समझता है और ऐसा आदेश पारित करता है, जैसे वह उपयुक्त समझे।

(7) दावा अधिकरण, व्यक्तिगत चोट के मामलों में, यदि और उपचार की आवश्यकता है, तो ऐसी रकम जो ऐसे उपचार के व्ययों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो, को आहरित करने की अनुज्ञा प्रदान करके लिखित में कोई आदेश पारित कर सकेगा।

(8) दावा अधिकरण, रकम के विनिधान के विषय में, दावेदार के लिए अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने की दृष्टिगत राज्य या केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक सेक्टर के उपक्रमों, जो ब्याज की उच्चतर दर का प्रस्ताव करते हों, में जमा करने के आदेश पारित करेगा।

(9) दावा अधिकरण, ऐसी राशि के विनिधान में निदेश देगा कि निक्षेपों पर ब्याज ऐसे संस्थानों द्वारा, दावा अधिकरण की सूचना के अधीन, दावेदारों को या अवस्यक दावेदारों के संरक्षकों को प्रत्यक्षतः संदत्त किया जाए।”।

**12. मूल नियमों के राजभाषा पाठ के नियम 232 का प्रतिस्थापन.**—उक्त नियमों के नियम 232 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

**“232 दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील का प्रारूप और रीति.**—(1) दावा अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील, अपीलार्थी द्वारा या इस निमित्त ऐसे अपीलार्थी द्वारा सम्यक रूप से सशक्त अधिवक्ता द्वारा, हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष, प्रस्तुत की जाएगी और इसके साथ अधिनिर्णय की प्रति भी संलग्न की जाएगी।

(2) ज्ञापन में अपील के आधार किसी तर्क या विवरण के बिना संक्षिप्त रूप से विनिर्दिष्ट किए जाएंगे और ऐसे आधारों को क्रमवर्ती रूप में संख्याकित किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) और (2) में यथा उपबंधित के सिवाय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची में आदेश 41 और 21 के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित उपरोक्त निर्दिष्ट अपीलों को भी लागू होंगे।”।

**13. मूल नियमों के राजभाषा पाठ के नियम 233 का प्रतिस्थापन.**—उक्त नियमों के नियम 233 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

**“233 फीस.**—(1) धारा 166 के अधीन आवेदन पर प्रतिकर के संदाय के लिए कोई भी न्यायालय फीस उदगृहीत नहीं की जाएगी।

(2) नस्तियों के निरीक्षण के लिए प्रभारित की जाने वाली न्यायालय फीस की राशि प्रत्येक मामले में प्रथम घण्टे के लिए 20 रुपये और प्रत्येक पश्चात्तर्वर्ती घण्टों के लिए दस रुपये होगी।

(3) सम्बन्धित पक्षकारों को साक्ष्य की कार्बन प्रतियां यदि मांगी जाती हैं, प्रति पृष्ठ दो रुपये न्यायालय फीस का संदाय करने पर दी जाएगी और ऐसी प्रतियों को प्राप्त करने के लिए आवेदन पर दस रुपये की न्यायालय फीस देनी होगी।

(4) अन्तिम आदेश के अधिनिर्णय या मध्यवर्ती आदेश या दावा अधिकरण के पास दायर किसी दस्तावेज की अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए प्रति पृष्ठ दो रुपये की राशि न्यायालय फीस के रूप में प्रभारित की जाएगी।”।

**14. नियम 234 का अन्तः स्थापन.**—उक्त नियमों के नियम 234 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

**“234 क. अभिलेखों, रजिस्ट्रों और प्रमाणित प्रतिलिपियों की अभिरक्षा और परिरक्षण.**—(1) मामलों से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज और अभिलेख अधिनिर्णय यदि कोई प्रदान किया गया हो, के समाधान होने की छह वर्ष की अवधि के लिए या निर्णय और अधिनिर्णय के अन्तिम विनिश्चय, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् बारह वर्ष की अवधि के लिए अभिलेख कक्ष में परिरक्षित किए जाएंगे।

(2) दावा अधिकरण, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले आपेक्षित समस्त रजिस्ट्रों के अतिरिक्त निम्नलिखित रजिस्टर का भी अनुरक्षण करेगा, अर्थात्:—

(i) दायित्व की कोई गलती नहीं के सिद्धान्त पर

(ii) अंतरिम निर्णय के आवेदनों के लिए रजिस्टर; और

(iii) अधिकरण में चैकों के माध्यम से संदायों को जमा करने के लिए रजिस्टर।

(3) मृत्यु, स्थायी निशक्तता, चोट और सम्पत्ति की क्षति के आधारों पर दावा याचिकाएं एक पृथक रजिस्टर में दर्ज की जाएगी।

(4) उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रमाणित प्रति जारी करने संबंधित नियम, दावा अधिकरणों के यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।”

**15. उक्त नियमों के हिमाचल प्रदेश प्ररूप 52 एम0ए0सी0टी0ए0 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:—**

“प्ररूप हिमाचल प्रदेश एम0 ए0 सी0 टी0 (ए0)

(नियम 214 और 214 च (6) देखें)

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष प्रतिकर के लिए आवेदन

सेवा में,

दावेदार(रों)  
के फोटो

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

महोदय/महोदया,

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .....  
निवासी ..... मोटरयान दुर्घटना में चोटिल होने पर मुझे आयी चोट के लिए प्रतिकर प्रदान करने के लिए एतद्वारा आवेदन करता /करती हूँ।

चोट यान आदि की बाबत आवश्यक विशिष्टियां निम्न प्रकार से है:-

मैं/ हम .....पिता/माता/पुत्र/पुत्री(पुत्रियाँ)/विधवा, .....निवासी.  
.....मोटर यान दुर्घटना में श्री/श्रीमती/कुमारी .....की मृत्यु के कारण प्रतिकर प्रदान करने के लिए श्रीमती/ कुमारी .....जिनकी मोटरयान दुर्घटना में मृत्यु हुई है, के विधिक प्रतिनिधि के रूप में एतद्वारा आवेदन करता हूँ/करते हैं। मृतक/चोटिल व्यक्ति/यान आदि के बारे में आवश्यक विशिष्टियां निम्न प्रकार से है:—

1. चोटिल/मृतक व्यक्ति का नाम और पिता का नाम (विवाहित महिला और विधवा की दशा में पति का नाम).....
2. चोटिल/मृतक व्यक्ति का पूरा पता.....
3. चोटिल/मृतक व्यक्ति की आयु.....
4. चोटिल/मृतक व्यक्ति का व्यवसाय .....
5. मृतक के नियोजक का नाम और पता, यदि कोई हो.....
6. चोटिल/मृतक व्यक्ति की मासिक आय .....
7. क्या वह व्यक्ति जिसके बारे में प्रतिकर का दावा किया गया है, आयकर दाता है ? यदि ऐसा है, तो आयकर की राशि दर्शित करें (दस्तावेजों साक्ष्य द्वारा समर्थित हों).....
8. दुर्घटना का स्थान, तारीख और समय .....
9. पुलिस थाने का नाम और पता जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना हुई या मामला रजिस्टर किया गया था .....
10. क्या व्यक्ति जिसके बारे में प्रतिकर का दावा किया गया है, दुर्घटना में अन्तर्वलित मोटरयान द्वारा यात्रा कर रहा था ? यदि ऐसा है तो यात्रा के आरम्भ और गंतव्य स्थान का नाम दें .....

\_\_\_\_\_

11. आई चोटें और अक्षमता, यदि कोई है .....
12. चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी, यदि कोई हो, जिसने मृतक/चोटिल व्यक्ति की देखरेख की है, का नाम और पता .....
13. ईलाज की अवधि और उस पर उपगत व्यय, यदि कोई हो (दस्तावेजों साक्ष्य द्वारा समर्थित हो) .....
14. दुर्घटना में अन्तर्वलित मोटरयान की रजिस्ट्रेशन संख्या और उसका प्रकार .....
15. मोटरयान के बीमाकर्ता का नाम और पता .....
16. मोटरयान के स्वामी का नाम और पता.....
17. क्या स्वामी/बीमाकर्ता के पास कोई दावा दायर किया गया है ? यदि ऐसा है तो उसका क्या परिणाम निकला.....
18. आवेदक का नाम और पता.....
19. मृतक/चोटिल व्यक्ति से सम्बन्ध .....
20. मृतक/चोटिल व्यक्ति की सम्पत्ति पर हक .....
21. दावाकृत प्रतिकर की राशि और दावे का आधार .....
22. क्या पुलिस और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों से विहित प्ररूप पर रिपोर्ट प्राप्त की गई है? (यदि ऐसा है तो संलग्न करें).....
23. क्या नियम 214 में उल्लिखित दस्तावेजों को सूचीबद्ध कर सम्यक रूप से संलग्न किया है (विवरण दें).....
24. कोई अन्य सूचना जो दावे के निपटान के लिए आवश्यक/सहायक हो सकती है.....
25. दावा आवेदन विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण और आधार जिन पर विलम्ब के लिए माफी दावा किया गया है.....
26. दुर्घटना के कारण का संक्षिप्त विवरण.....

आवेदक (कों) के हस्ताक्षर  
या अंगूठा निशान

सत्यापन

.....में.....के.....दिन

यह सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदन की अन्तर्वस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है।

आवेदक (कों) के हस्ताक्षर  
या अंगूठा निशान

**टिप्पणी:—**(1) आवेदक, दावे के आवेदन में उल्लिखित-प्रत्यार्थियों की संख्या के बराबर, प्रत्यार्थियों को नोटिस के साथ उन्हें भेजने के लिए आवेदन की अतिरिक्त प्रतियां संलग्न करेगा।

(2) आवेदन दुर्घटना होने के छः महीने के भीतर दायर किया जाएगा और आवेदन को विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए कारण दिए जाएं।

(3) आवेदक रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा अपने आवेदन मोटर यान दावा अधिकरण को भेज सकेंगे।

**16. प्ररूप एच. पी. 52 एम.ए.सी.टी.(बी)से एच पी प्ररूप 52 एम. ए. सी. टी. (जे) का अन्तः स्थापन.—**उक्त के प्ररूप एच. पी. प्ररूप-52 एम. ए. सी. टी. (ए) के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

प्ररूप एच.पी.एम.ए.सी.टी.(बी)  
(नियम-214 और 214-अ (घ) देखें)

अन्वेषक पुलिस अधिकारी को आदेश मोटर यान दावा अधिकरण.....,हिमाचल प्रदेश के समक्ष।

केस संख्या.....

.....बनाम.....

विषय:.....प्रथम इतिला रिपोर्ट संख्या.....

सेवा में

प्रभारी  
पुलिस थाना.....

उपरोक्त वर्णित दावा याचिका दुर्घटना से सम्बन्धित प्रतिकर के संदाय की पूर्ति हेतु इस दावा अधिकरण में प्रस्तुत की गई है, जो आपके द्वारा उपरोक्त कथित प्रथम इतिला रिपोर्ट के माध्यम से अन्वेषण की विषय वस्तु कथित की गई है;

विधि आपको मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 160 के उपबन्धों के अधीन सम्बद्ध पक्षकारों को और केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 150 और हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 215-अ के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 158 की उप-धारा (6) के उपबन्धों के अधीन इस अधिकरण को निम्न स्वरूप में दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए व्यादिष्ट करती है—

- (1) यान जिसके कारण दुर्घटना हुई का पहचान चिन्ह और अन्य विशिष्टियां
- (2) व्यक्ति जो दुर्घटना के समय उसे चला/उपयोग कर रहा था, का नाम और पता
- (3) व्यक्ति, जो चोटिल हुआ था का नाम और पता या क्षतिग्रस्त सम्पति का विवरण
- (4) प्रथम इतिला रिपोर्ट की प्रति;
- (5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट सहित उससे संलग्न दस्तावेज अर्थात्, रिपोर्ट पोस्टमार्टम, यांत्रिक जांच रिपोर्ट, के लिए गए फोटोग्राफ, तैयार किया गया स्थल-नक्शा, चालन अनुज्ञप्ति रजिस्ट्रीकरण, प्रमाण-पत्र, परमिट, बीमा पॉलिसी, सत्यापन, यदि कोई है और



(6) अभिग्रहित कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज।

अतः एतद्वारा आपको इस संसूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर समस्त उपर्युक्त दस्तावेजों की आपके कार्यालय की मोहर सहित आपके द्वारा हस्ताक्षरित सम्यक रूप से अनुप्रमाणित स्पष्ट सुपाठ्य छाया प्रतियों सहित प्ररूप एच.पी.एम.ए.सी.टी (ई) में सूचना इस दावा अधिकरण को भेजने का निदेश दिया जाता है।

मेरे हस्ताक्षर और मुहर द्वारा.....दिन को जारी।

(मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण)

एच.पी. प्ररूप 52 एम.ए.सी.टी.(सी)  
(नियम 214-अ (ड.) और 214-ई (क) देखें)

अन्वेषक पुलिस अधिकारी को आवेदन

मामला संख्या (केस संख्या).....

शीर्षक.....बनाम.....

विषय:..... प्रथम इतिला रिपोर्ट संख्या.....

सेवा में,

प्रभारी  
पुलिस थाना.....

महोदय,

आवेदक, दुर्घटना से सम्बन्धित प्रतिकर के संदाय की पूर्ति के लिए उपरोक्त वर्णित दावा याचिका, जिसे विशिष्टियों की ऊपर दी गई प्रथम इतिला रिपोर्ट में अन्वेषण की विषय-वस्तु कथित किया गया है, मैं दावेदार/बीमा-कम्पनी के रूप में एक पक्षकार है;

और विधि आपको केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 150 और हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 215-अ के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 160 के उपबधों के अधीन सम्बद्ध पक्षकारों को निम्न स्वरूप में दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए व्यदिष्ट करती है:—

- (1) यान, जिस के कारण दुर्घटना हुई, की पहचान के चिन्ह और अन्य विशिष्टियां;
- (2) व्यक्ति, जो दुर्घटना के समय उसे चला/उपयोग कर रहा था, का नाम और पता
- (3) व्यक्ति, जो चोटिल हुआ था, का नाम और पता या क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का विवरण;
- (4) प्रथम इतिला रिपोर्ट की प्रति;

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट सहित उससे संलग्न दस्तावेज अर्थात् रिपोर्ट/पोस्टमार्टम रिपोर्ट, यांत्रिक जांच रिपोर्ट, लिए गए फोटोग्राफ, तैयार किया गया स्थल-नक्शा, चालन अनुज्ञप्ति, पंजीकरण (रजिस्ट्रीकरण) प्रमाण-पत्र, परमिट, बीमा पॉलिसी, सत्यापन, यदि कोई हो, आदि और

(6) अभिग्रहित कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज।

अतः अधोहस्ताक्षरधारी अनुरोध करता है कि प्ररूप एच.पी.एम.ए.सी.टी.(डी) में अपेक्षित सूचना इस संसूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर उसे भेजने की कृपा करें।

भवदीय

( )

तारीख:

पूरा नाम और पता

एच.पी. प्ररूप 52 एम.ए.सी.टी.(डी)  
(नियम 214-आ देखें)

दुर्घटना सूचना रिपोर्ट

भाग-I

1. प्रथम इतिला रिपोर्ट संख्या, तारीख और आरोपित धाराएं.....
2. पुलिस थाना का नाम.....
3. दुर्घटना की तारीख, समय और स्थान.....
4. चोटिल/मृत व्यक्ति का नाम और उसके पिता का नाम और पता.....(विवाहित महिला और विधवा की दशा में पति का नाम)
5. उल्लंघनकर्ता यान (यानों) के चालक का नाम और पता.....
6. उल्लंघनकर्ता यान (यानों) के चालक की चालन अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां:
  - (क) चालन अनुज्ञप्ति संख्या.....
  - (ख) अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि.....
  - (ग) जारीकर्ता प्राधिकारी.....
7. उल्लंघनकर्ता यान (यानों) के स्वामी का नाम और पता:.....
8. उल्लंघनकर्ता मोटर यान (यानों) की विशिष्टियां
  - (क) दुर्घटनाग्रस्त यान (यानों) की रजिस्ट्रीकरण संख्या और प्रकार:
  - (ख) इंजन संख्या.....
  - (ग) चैसी संख्या.....
  - (घ) वाणिज्यिक यान की दशा में परमिट और उपयुक्तता की विशिष्टियां

9. उल्लंघनकर्ता यान (यानों) के बीमा की विशिष्टियां :
  - (क) पॉलिसी/कवर नोट संख्या.....
  - (ख) पॉलिसी की विधिमान्यता की अवधि.....
  - (ग) बीमा कम्पनी का नाम और पता.....
10. चोटिल/मृत व्यक्ति की आयु.....
11. चोटिल/मृत व्यक्ति का व्यवसाय.....
12. चोटिल/मृत व्यक्ति की मासिक आय.....
13. क्या वह व्यक्ति जिस की बाबत में प्रतिकर का दावा किया गया है, आयकर संदाय करता है? यदि ऐसा है तो आयकर की रकम निर्दिष्ट करें.....
14. मृत्यु की दशा में मृतक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों के नाम, आयु, पता और सम्बन्ध.....
15. यदि चोट लगी है, तो उसका स्वरूप, किया गया उपचार और अक्षमता, यदि कोई है.....
16. चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी, जिसने चोटिल व्यक्ति की देखरेख की है, का नाम और पता.....
17. कोई अन्य अतिरिक्त सूचना.....

## भाग—II

दुर्घटना सूचना रिपोर्ट के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अधीन रिपोर्ट
2. प्रथम इतिला रिपोर्ट
3. चिकित्सा विधिक प्रमाण—पत्र
4. फोटोग्राफ
5. स्थल नक्शा
6. यांत्रिक निरीक्षण रिपोर्ट
7. अभिग्रहण (सीजर) मेमो

मृत्यु की दशा में

8. मृतक की आयु का प्रमाण जो कि निम्न प्ररूप में हो सकेगा:
  - (i) जन्म प्रमाण—पत्र
  - (ii) दसवीं पास का प्रमाण—पत्र

- 
- (iii) ग्राम पंचायत से प्रमाण-पत्र (यदि अशिक्षित है)
- (iv) मृतक का फोटोयुक्त पहचान-पत्र
9. मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट
10. मृतक की आय का प्रमाण जोकि निम्न प्ररूप में हो सकेगा:
- (i) वैतनिक कर्मचारियों के लिए वेतन पर्ची (पे स्लिप)/वेतन प्रमाण-पत्र
- (ii) बैंक की अंतिम छः मास की विवरणी
- (iii) आयकर विवरणी
- (iv) तुलन-पत्र
11. मृतक के विधिक प्रतिनिधियों के प्रमाण :
- (i) नाम
- (ii) आयु
- (iii) पता
- (iv) सम्बन्ध
12. उपचार रिकार्ड, चिकित्सा बिल और अन्य व्यय
- चोट की दशा में
13. चोटिल व्यक्ति की आयु का प्रमाण जो कि निम्न प्ररूप में हो सकेगा:
- (i) जन्म प्रमाण-पत्र
- (ii) दसवीं पास का प्रमाण-पत्र
- (iii) ग्राम पंचायत से प्रमाण-पत्र (यदि अशिक्षित है)
- (iv) चोटिल व्यक्ति का फोटो युक्त पहचान-पत्र।
14. दुर्घटना के समय चोटिल व्यक्ति की आय का प्रमाण जो कि निम्न प्ररूप में हो सकेगा:
- (i) वैतनिक कर्मचारियों के लिए वेतन पर्ची/वेतन प्रमाण-पत्र
- (ii) चोटिल व्यक्ति की अंतिम छः मास की बैंक विवरणी
- (iii) आयकर विवरणी
- (iv) तुलन-पत्र

15. चिकित्सा विधिक प्रमाण-पत्र

16. उपचार रिकार्ड, चिकित्सा बिल और अन्य व्यय-थाना [प्रभारी/अन्वेषण](#) अधिकारी (दीर्घ अवधि उपचार की दशा में) विवरणियां भी दर्ज करेगा ताकि प्रार्थी ऐसे बिलों का दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सके।

17. निशक्तता प्रमाण-पत्र

18. कार्य से अनुपस्थिति का सबूत जहां चोट के कारण आय की हानि का दावा किया गया है, जो कि निम्न प्ररूप में हो सकेगा:

(i) नियोक्ता से प्रमाण पत्र

(ii) हाजिरी रजिस्टर से उद्धरण

19. उपरोक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की पुष्टि से सम्बंधित रिपोर्ट।

(थाना प्रभारी)

सत्यापन  
.....में.....के.....दिन

यह सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट की विषय-वस्तु मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और ठीक है और भाग-II में वर्णित दस्तावेजों को सही सत्यापित किया जाता है।

(थाना प्रभारी)

एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी. (इ)  
(नियम 214-इ (क) और (ख), 214-ई (ग) और (घ), 214-उ देखें)

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की रिपोर्ट

मामला संख्या.....

शीर्षक.....बनाम.....

सेवा में,

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

महोदय,

यह उपरोक्त उल्लिखित मामले में.....के आदेश/आवेदन के संदर्भ में है। अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

1. यान की विशिष्टियां:-

(क) रजिस्ट्रीकरण संख्या:

- (ख) वाहन का प्रकार:
- (ग) बनावट और मॉडल:
- (घ) इंजन संख्या:
- (ङ) चैसिस संख्या:
- (च) यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी का पूरा नाम और पता:
2. चालन अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां:
- (क) धारक की चालन अनुज्ञप्ति संख्या और जारी करने/अवसान की तारीख:
- (ख) अनुज्ञप्ति धारक का नाम और पता:
- (ग) जारी करने वाले प्राधिकारी की विशिष्टियां:
- (घ) यदि सार्वजनिक सेवा यान है, तो उसकी बैज संख्या:
- (ङ) विस्तृत रिपोर्ट, यदि उल्लिखित विशिष्टियां वास्तविक नहीं पाई गई हैं:
3. रूट परमिट की विशिष्टियां:
- (क) परमिट (अनुज्ञा-पत्र) संख्या और अवसान की तारीख:
- (ख) परमिट (अनुज्ञा-पत्र) धारक का नाम और पता:
- (ग) परमिट (अनुज्ञा-पत्र) की किस्म (प्रकार):

(रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी)

सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु इस कार्यालय के अभिलेख के अनुसार सही है।

(रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी)

तारीख:

-----

एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(एफ)  
(नियम 214-ग(क) देखें)

मामला संख्या:.....

शीर्षक:.....बनाम (वरसेज़).....

विषय.—(1) यान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यता.....के पक्ष में.....संख्या.....  
चालन अनुज्ञप्ति संख्या.....तक विधिमान्य.....अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा.....जारी  
किया गया।

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

.....  
.....

आदेश

इस दावा अधिकरण में अवधि कथित रूप से अन्तर्वलित मोटर यान दुर्घटना के सम्बन्ध में प्रतिकर के संदाय की मांग करने वाली उपरोक्त वर्णित दावा याचिका प्रस्तुत की गई है, जिसकी विशिष्टियां उपरोक्त नामित है;

और, यान को आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय द्वारा रजिस्ट्रीकृत हुआ कथित किया गया है और चालन अनुज्ञप्ति/परमिट आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय द्वारा जारी किया गया कथित किया गया है;

और, उक्त चालन अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा-पत्र के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अभिलेखों को केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अधीन आपके नियंत्रणाधीन उक्त अधिकारी द्वारा अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित है;

और, उक्त दस्तावेज से संबंधित अपेक्षित सूचना माटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 168 के उपबंधों के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए इस दावा अधिकरण द्वारा अपेक्षित है जिसे आप हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 215-ख के साथ पठित केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 149 के निबन्धनों के अनुसार प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं;

अतः, आपको उपरोक्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र/चालन अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा पत्र के बारे में किसी प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित समर्थक दस्तावेजों की प्रतियां कार्यालय मुहर सहित पूर्ण सूचना इस संसूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर इस दावा अधिकरण को प्रस्तुत करने का एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

इसे.....को.....दिवस को मुहर सहित मेरे हस्ताक्षराधीन से दिया गया ।

एम.ए.सी.टी.

-----  
एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(जी)  
(नियम 214-ग(ख) और 214-घ(ग) देखें)

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवेदन

मामला संख्या.....

शीर्षक.....बनाम.....

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी,

.....  
.....

विषय.—यान संख्या.....अनुज्ञा पत्र संख्या.....चालन अनुज्ञप्ति संख्या.....  
.....की बाबत.....

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त वर्णित दावा याचिका में दुर्घटना में अन्तर्वलित मोटर यान के संबंध में प्रतिकर को संदाय करने के लिए एक पक्षकार के रूप में अभियोजित किया गया है, जिसकी विशिष्टियाँ उपरोक्त नामित है;

और, उपर्युक्त यान को आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया कथित किया गया है, और उपर्युक्त चालन अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा पत्र भी आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय द्वारा जारी किया गया कथित है(जो लागू नहीं हो उसे काट दें);

और, उक्त चालन अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा पत्र के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित अभिलेखों को केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अधीन आपके कार्यालय द्वारा अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित है;

और, उपर्युक्त दस्तावेज से संबंधित अपेक्षित सूचना इस दावा अधिकरण द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 168 के उपबंधों के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है, जिसे आप हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 215—ख के साथ पठित केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 149 के अनुसार प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं;

अतः, अधोहस्ताक्षरी अनुरोध करता है कि उपरोक्त प्रमाण—पत्र/चालन अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा—पत्र के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में आपके कार्यालय मुहर सहित सम्यक रूप से अनुप्रमाणित हस्ताक्षर द्वारा दस्तावेजों की प्रतियों के समर्थन में पूर्ण सूचना इस आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी।

आवेदक  
(पूरा नाम, विवरण और पता दिया जाए)

एच.पी. प्ररूप—52 एम.ए.सी.टी.(एच)  
(नियम 215—च(3) देखें)  
पक्षकारों की उपस्थिति के लिए नोटिस

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, हिमाचल प्रदेश के समक्ष

मामला संख्या .....  
शीर्षक संख्या.....बनाम.....

नोटिस

विषय: मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 158(6) के अधीन पुलिस रिपोर्ट को  
मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166(4) के अधीन दावा मामला माना  
जाना ।

संदर्भ प्रथम इतिला रिपोर्ट  
पुलिस थाना.....

सेवा में,

.....  
.....  
(नाम, विवरण और निवास स्थान )



उक्त पुलिस थाने के थाना प्रभारी से मोटर यान के उपयोग में अन्तर्वलित दुर्घटना के संबंध में प्रथम इतिला रिपोर्ट के संदर्भ में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 158(6) के अधीन एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

और, उपर्युक्त रिपोर्ट को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166(4) के उपबंधों के अनुसार इस दावा अधिकरण द्वारा दावा मामले के रूप में माना गया है, जिसमें.....तारीख को..... पूर्वाह्न/अपराह्न पर मामले की आगामी कार्यवाहियों के लिए अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने हेतु आपको बुलाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है;

अतः, आपको एतद्वारा, इस दावा अधिकरण के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से या सम्यक रूप से अनुदेशित किसी अधिवक्ता जो उपरोक्त दावा मामले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, के माध्यम से उपर्युक्त तारीख और समय पर उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है;

और, चूंकि दावा मामले की सुनवाई हेतु आपकी उपस्थिति के लिए नियत तारीख निर्धारित की गई है, और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त तारीख को या से पूर्व दावा मामले की पूर्ण विशिष्टियाँ प्रकट करते हुए वचनबन्ध दायर करें, जिसे आपके द्वारा या आपके विरुद्ध वाद हेतुक की बाबत या तो अधिमानित किया गया हो या अधिमानित किया जा रहा है।

ध्यान दें कि उपरोक्त उल्लिखित तारीख को और समय पर आपकी उपस्थिति में कोई चूक होने पर दावा मामले को सुना जाएगा और आपकी अनुपस्थिति में ही अवधारित कर दिया जाएगा।

इसे.....को .....दिवस को इस अधिकरण की मुहर सहित मेरे हस्ताक्षराधीन दिया गया।

एम.ए.सी.टी.

एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(आइ)

(नियम 217 देखें)

विरोधी पक्षकार को नोटिस

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण हिमाचल प्रदेश के समक्ष

मामला संख्या:.....

शीर्षक.....बनाम.....

नोटिस

सेवा में,

.....  
.....  
.....  
(नाम, विवरण और निवास स्थान)

.....ने.....को प्रतिवादी के रूप में अभियोजित करते हुए मोटर दुर्घटना दावे का मामला संस्थित किया है (दायर दस्तावेजों सहित आवेदन की प्रतियां संलग्न हैं) जिसे दावा अधिकरण के समक्ष.....को.....पूर्वाह्न/अपराह्न पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निदेश हुआ है।

अतः, आपको एतद्वारा व्यक्तिगत रूप से या समयक् रूप से अनुदेशित किसी अधिवक्ता और जो दावा मामले से सम्बन्धित समस्त सारवान प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो, के माध्यम से दावा अधिकरण के समक्ष उपर्युक्त तारीख और समय पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

और चूंकि आपकी उपस्थिति के लिए नियत तारीख दावा मामले की सुनवाई हेतु निर्धारित की गई हैं, अतः आप उस तारीख को या से पूर्व आवेदन में किए गए दावे से सम्बन्धित लिखित कथन के साथ-साथ उन सभी तथ्यों, जिन पर आपको प्रतिरक्षण पर आप विश्वास करते हैं, के समर्थन में, दस्तावेजों की सूची में समयक् रूप से प्रविष्ट समस्त दस्तावेज दाखिल कर सकेंगे, जिसके पश्चात हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1989 के नियम 219 में यथा उपवांछित के सिवाय किन्हीं अतिरिक्त दस्तावेजों पर विश्वास करना अनुज्ञेय नहीं होगा।

ध्यान दें कि उपरोक्त उल्लिखित तारीख को आपकी उपस्थिति में कोई चूक होने पर दावा मामले को आपकी अनुपस्थिति में सुना जाएगा और अवधारित किया जाएगा।

इसे.....को .....दिवस को अधिकरण की मुहर सहित मेरे हस्ताक्षराधीन दिया गया है।

एम.ए.सी.टी.

एच.पी. प्ररूप-52 एम.ए.सी.टी.(जे)  
(नियम 224-ख देखें)

चिकित्सीय परीक्षा के लिए निदेश  
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण हिमाचल प्रदेश के समक्ष

मामला संख्या (केस सं0) .....

शीर्षक.....बनाम.....

दावेदार(रों) का  
फोटो

सेवा में,

.....  
.....  
.....

आदेश

इस दावा अधिकरण में मोटर यान के उपयोग से अन्तर्वलित दुर्घटना के सम्बन्ध में प्रतिकर के संदाय की पूर्ति के लिए उपर्युक्त दावा याचिका की गई है और दावेदार पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री.....आयु..  
.....निवासी....., जिसके नमूना हस्ताक्षर/अंगूठा छाप वाली फोटो ऊपर चिपकाई गई है, को उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप चोटिल हुआ अभिकथित किया गया है, जिसे.....(अस्पताल का नाम) में चिकित्सा..... विधिक प्रमाण-पत्र संख्या.....तारीख.....में अभिलिखित किया गया है;

और, दावा याचिका की जांच के प्रयोजन के लिए यह दावा अधिकरण द्वारा उक्त दावेदार द्वारा उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप निशक्त:ता परिमाण और मात्रा अभिनिश्चित करना आवश्यक समझा गया है;

अतः, हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियमों के अनुक्रम में, इस दावा अधिकरण में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी आपको अपने अस्पताल में किसी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा

अधिकारियों के बोर्ड द्वारा उक्त दावेदार का परीक्षण करवाने हेतु निर्देशित करता है और उपरोक्त पहलुओं पर इस निदेश की प्राप्ति के 15 दिन की अवधि के भीतर इस दावा अधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश देता है।

तारीख.....को मेरे नाम और इस अधिकरण की मोहर सहित जारी किया गया है।

एम.ए.सी.टी.

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / —  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन)।

*[Authoritative English Text of this Department Notification No. TPT-E(3)-32/2018-II dated 23-9-2021 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].*

## TRANSPORT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-02, the 23rd September, 2021*

**No. TPT-E (3)-32/2018-II.**—In exercise of the powers conferred by section 176 read with sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No 59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicle Rules, 1999, published in the Rajpatra (Extra Ordinary), Himachal Pradesh, dated 27th July, 1999 *vide* this department Notification No. 5-24/88-TPT-III dated 12th July, 1999, which are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for the information of the General Public;

If any person, likely to be affected by these draft rules, have any objection(s) or suggestion(s) to make with regard to these rules, he may send the written objection(s) or suggestion(s) to the Addl. Chief Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, within a period of seven days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the above stipulated period, shall be taken into consideration by the Government of Himachal Pradesh before finalizing the said draft rules, namely:—

### Draft Rules

**1. Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicle (Third Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

**2. Substitution of rule 215.**—For rule 215 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, (hereinafter referred to as the 'said rules') the following shall be substituted, namely:—

“215. Application for claim of compensation.-(1) Every application for claim of compensation to be made under section 166 shall be in H.P. FORM LII MACT (A), accompanied by spare copies (equal to the number of respondents cited in the claim application).

(2) There shall be appended to every such application,

(a) all the documents on which the applicant relies in context of his claim, entered in a properly prepared list of documents:

Provided that the Claims Tribunal may not allow the applicant to rely in support of his claim, on any document not filed with the application, unless it is satisfied that for good or sufficient cause, he was prevented from filing such document earlier;

(b) proof of identity of the applicant(s) to the satisfaction of the Claims Tribunal, unless exempted from doing so for reasons to be recorded by it in writing;

(c) passport size photograph(s) of the applicant(s) duly attested by an Advocate or a Gazetted Officer;

(d) reports obtained from investigating police officer, and registering authority; and if no such report(s) have been obtained, reasons thereof; and

(e) medical certificate of injuries, or the effect thereof.

(3) The Claims Tribunal may also require the applicant to furnish the following information to satisfy itself that false or a collusive claim has not been preferred:—

(a) full particulars of all earlier accidents in which the applicant or the person deceased, as the case may be, has been involved;

(b) the amount of compensation paid in such earlier accidents, name and particulars of the victim, and of the person, who paid the damages; and

(c) connection of persons mentioned in clause (b), if any, with the applicant.

(4) Any application which is found defective on scrutiny, may be returned by the Claims Tribunal, for re-submission after removing the defects within a specified period but not exceeding two weeks time.

(5) Every application for compensation shall be registered separately in the prescribed register.”.

**3. Insertion of Rule 215A to 215 F.**—In the said rules, after rule 215, the following rules shall be inserted namely:—

**“215-A. Duties of investigating Police Officer in motor accident cases.-** (1) It shall be the duty of the investigating police officer to use modern technology while making investigation, including the following, as expeditiously as possible, to.—

(a) get the scene of accident cordon off and then photographed from such angles as to clearly depict, and in case of inability to do so, prepare a site plan, drawn to scale, as to

- indicate the lay-out and width, etc. of the road(s) or place, as the case may be, the position of vehicle(s), or person(s), involved in an accident and such other facts as may be relevant, so as to preserve the evidence in this regard, for the purposes of proceedings before the Claims Tribunal;
- (b) gather full particulars of the insurance certificate/policy in respect of the motor vehicle involved in the accident and to require the production of the documents mentioned in sub-section (1) of section 158 of the Act, and thereupon either to take the same in possession against receipt, or to retain the duly attested photocopies of the same;
  - (c) verify the genuineness of the documents mentioned in clause (b) by obtaining confirmation in writing from the office/authority purporting to have issued the same;
  - (d) submit detailed report regarding an accident to the Claims Tribunals, in Part- I of HP FORM LII MACT (D) by not later than thirty days of the receipt of order in HP FORM LII MACT (B), accompanied by requisite documents, which shall include copy of report under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), medico legal certificate, post-mortem report (in case of death), first information report, photographs, site plan, photocopies of documents mentioned in clause (c), report regarding confirmation of genuineness thereof, if received, or otherwise action taken; and
  - (e) furnish to the applicant all information and particulars about the accident in Part- I of HP FORM LII MACT (D), within thirty days, on receiving the application in HP FORM LII MACT (C), by the person, who wishes to make an application for compensation and who is involved in an accident, or his next of kin, or the legal representative of the deceased, or the insurance company, as the case may be:

Provided that such information shall be given to the insurance company on payment of a fees of rupees ten per page.

(2) The provision of sub-rule (1), shall be construed as duties given under the Himachal Pradesh Police Act, 2007 and the rules framed there under and any breach thereof, shall entail consequences envisaged in the said Act.

**215-B. Investigation of Motor accident Claims.**-Notwithstanding anything contained to the contrary in any other rules in force, the motor accident claims shall be investigated by the police in the following manner,—

(1) On receipt of the information about a motor accident, the Investigating Police Officer shall visit the site of accident, make inspection of the site, take photographs of the site from all angles, prepare a site plan drawn to a scale, to indicate the lay-out of the road or place, as the case may be, the position of vehicle or person as the case may be, such other facts, as may be relevant and shall also examine the eye-witnesses in order to preserve complete evidence with regard to the accident.

- (2) The Investigating Police Officer shall collect complete particulars and documents,—
  - (i) date, time and place of the accident;
  - (ii) particulars of the person injured or deceased in the accident;
  - (iii) name and address of the driver of the offending vehicle;

- 
- (iv) driving license of the driver of the offending vehicle;
  - (v) names and address of the owner of the offending vehicle;
  - (vi) certificate of registration of the offending vehicle;
  - (vii) insurance policy or in the alternative cover note or certificate of insurance of the offending vehicle;
  - (viii) fitness certificate and the permit (in the case of a commercial vehicle);
  - (ix) names and addresses of the witnesses of the accident;
  - (x) circumstances of the occurrence of the accident;
  - (xi) In case of death of the victim,—
    - (a) proof of age of the deceased;
    - (b) death certificate;
    - (c) post-mortem report;
    - (d) proof of income of the deceased;
    - (e) details of the dependents, (i.e their age, occupation and marital status);  
and
    - (f) expenditure on treatment; and
  - (xii) in case of any injury to the victim;
    - (a) Medico legal Certificate;
    - (b) proof of age of the injured;
    - (c) proof of the income of the injured;
    - (d) nature of injuries suffered by such victim,
    - (e) treatment taken by the injured (including the discharge summary);
    - (f) disability certificate (if issued by a Government Hospital);
    - (g) expenditure on treatment, conveyance, special diet or on attendant etc; and
    - (h) proof of absence from work (on the basis of which loss of income on account of injury is being assessed or claimed) such as certificate from the employer and extracts from the attendance register or log record or like record.

(3) The Investigating Police Officer shall verify the authenticity of the documents mentioned in Part-II of HP FORM LII MACT (D) by obtaining confirmation in writing from the office or authority or person purporting to have issued the same or by such further investigation or verification, as may be necessary, for arriving at a conclusion of authenticity of the documents in question (including but not limited to verifying the license of the driver and permit of the vehicle, where applicable), from the registering authority.

(4) The registering authority shall verify the registration certificate, driving license, fitness and permit in respect of the offending vehicle within a period of fifteen days of the application being made by the Investigating Officer. The concerned hospitals shall issue the Medico legal Certificate and Post-Mortem Report to the investigating Officer within a period of fifteen days of the accident.

(5) The Investigating Police Officer shall complete the process of collection of the aforesaid documents specified in sub-rules (3) and (4) and their date of verification and shall complete the investigation of the criminal case within a period of thirty days of the date of accident. The Investigating Officer shall file the Accident Information Report in HP FORM LII MACT (D) before the Claims Tribunal within a period of Thirty days of the date of accident. The Accident Information Report shall be accompanied by requisite document (which shall include a copy of the report under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973, First Information Report with the police, Medico legal Certificate, Post-Mortem Report) (in the case of death), photographs, site plan, mechanical inspection report, seizure memos and documents mentioned in Part – II of HP FORM LII MACT (D) and also a report regarding confirmation of authenticity thereof, if received or otherwise action taken. Copy of the Accident Information Report, shall simultaneously be sent to the Insurance Company, victim or their claimant of the accident and owner or driver of the offending vehicle.

(6) Upon receipt of copy of Accident Information Report, the Insurance Company shall appoint a Designated Officer within a period of ten days. The Designated Officer shall be responsible for dealing or processing of the case and to pass a reasoned decision in writing about the amount payable in accordance with law within a period of twenty days from the date of his appointment.

(7) Where the Investigating Police Officer is unable to complete the investigation of the case within a period of thirty days for reasons beyond his control, such as cases of hit and run accidents, cases where the parties reside outside the jurisdiction of the court, or where the victim has suffered grievous injuries and is undergoing treatment, the Investigating Officer shall approach the Claims Tribunal, for extension of time whereupon the Claims Tribunal shall suitably extend the time in view of the facts of each case.

(8) If the offending vehicle is found to be un-insured, the owner and driver of the offending vehicle shall be persecuted under section 196 of the Act.

(9) If the driving license of the driver is found to be fake, the Investigating Police Officer shall prosecute the driver or such other persons involved in forging or issuance of a fake driving license.

(10) The Investigating Police Officer shall produce the driver, owner, claimant and eye-witness before the Claims Tribunal along with the Accident Information Report. However, if the police is unable to produce the owner, driver, claimant and eye-witness before the Claims Tribunal on the first date of hearing for reasons beyond its control, the Claims Tribunal, shall issue notice to them to be served through the Investigating Police Officer, for a date for appearance not later than

thirty days time. The Investigating Police Officer, shall give an advance notice to the concerned Insurance Company about the date of filing of the Accident Information Report before the Claims Tribunal so that the nominated counsel for the insurance company could remain present on the date of hearing before the Claims Tribunal.

(11) The Claims Tribunal, shall examine whether the Accident Information Report, is complete in all respects, and shall pass an appropriate order in this regard. If the Accident Information Report is not complete, the Claims Tribunal shall direct the Investigating Police Officer to complete the said report and shall fix a date for its completion.

(12) The Claims Tribunal shall treat the Accident Information Report filed by the Investigating Officer, as a claim petition under section 166(4) of the Act. However, where the police is unable to produce the claimants on the first date of hearing, the Claims Tribunal shall initially register the Accident Information Report as a miscellaneous application, which shall be registered, as a claim petition after the appearance of the claimants.

(13) The Claims Tribunal shall grant thirty days' time to the insurance Company to examine the Accident Information Report and to take a decision as to the quantum of compensation payable to the claimants in accordance with law. The decision shall be taken by the designated officer of the insurance company in writing and it shall be a reasoned decision. The designated officer of the insurance company shall place the written reasoned decision before the claims Tribunal within a period of as specified in sub rules (6) from the date of receipt of the copy of accident information report from the Investigation Officer.

(14) The compensation assessed by the Designated Officer of the Insurance Company, shall constitute a legal offer to the claimants and if the said amount is fair and acceptable to the claimants, the Claims Tribunal, shall pass a consent award and shall give thirty days' time to the Insurance Company to make the payment of the amount so awarded. However, before passing the consent award, the Claims Tribunal, shall ensure that the claimants are awarded just compensation in accordance with law. The claims Tribunal shall also pass an order with respect to the shares of the claimants and the mode of disbursement.

(15) If the claimants are not in a position to immediately respond to the offer of the Insurance Company, the Claims Tribunal shall grant them time not later than thirty days, to respond to the said offer.

(16) If the offer of the insurance company is not fair and acceptable to the claimants or if the insurance company has any defense available to it under law, the Claims Tribunal shall proceed to conduct an inquiry under sections 168 and 169 of the Act, and shall pass an award within a period of thirty days thereafter.

(17) Prohibition against release of Motor Vehicle involved in accident,—

- (a) No Court shall release a motor vehicle involved in an accident resulting in death or bodily injury or damage to property, when such vehicle is not covered by the policy of insurance against third party risks taken in the name of registered owner or when the registered owner fails to furnish copy of such insurance policy despite demand by investigating police officer, unless and until the registered owner furnishes sufficient security to the certification of the court to pay compensation that may be awarded in a claim case arising out of such accident.
- (b) Where the Motor vehicle is not covered by a policy of insurance against third risks, or when registered owner of motor vehicle fails to furnish copy of such policy in



circumstance mentioned in sub-rule (1), the motor vehicle shall be sold off in police auction by the Magistrate having jurisdiction over the area where accident occurred, on expiry of three months of the -vehicle being taken in possession by the investigating Police officer, and proceeds there of shall be deposited with the Claims Tribunal having jurisdictions over the area in question, within fifteen days for purpose of satisfying the compensation that may have been awarded, or may be awarded in the claim case arising out of such accident:

Provided where the vehicle involved in an accident is having issuance certificate and the driver of the said vehicle having a valid driving license then the Investigation Police Officer, shall release the vehicle on superdari at his own level.

(18) Any breach in duty by the police personnel shall be dealt with as provided in sub-rule (2) of rule 215-A.

**215-C. Duties of the Registering Authority.**—It shall be the duty of the concerned registering authority to,—

- (a) submit a detailed report in HP FORM LII MACT (E) to the Claims Tribunal regarding a motor vehicle involved in the accident or about the license of the driver of such vehicle, within a period of fifteen days of the receipt of order in HP FORM LII MACT (F); and
- (b) furnish the requisite information in HP FORM LII MACT (E) within a period of fifteen days from the date of receipt of an application in HP FORM LII MACT (G) from the person, who wishes to make an application for compensation, or who is involved in an accident arising out of use of his next of kin, or to the legal representative of the deceased, or to the insurance Company, as the case may be:

Provided that information shall be given to the insurance company on payment of rupees ten per page.

**215-D. Duties of the Insurance Company.**—It shall be the duty of the Divisional Manager of an insurance company after receiving information about the accident, or on receipt of notice from the Claims Tribunals under rule 218, to.—

- (a) make an application in H.P. FORM LII MACT (C) to the investigating police officer (with prescribed fees) to obtain complete information about the accident, at the earliest;
- (b) ascertain and verify the facts about insurance of motor vehicle(s) involved in the accident and inform about it to the Claims Tribunal within a period of fifteen days from the date of receipt of notice of the claim case;
- (c) move application before the concerned registering authority in H.P. FORM LII MACT (G) to obtain information about the motor vehicle involved, and the driving license held by the driver of such motor vehicle as per information available in H.P. FORM LII MACT (E);
- (d) deposit (with the written statement in the Claims Tribunal), the amount equivalent to the compensation awardable on the principle of no fault liability under section 140 of

the Act, in such cases, where the information is received in H.P. FORM II MACT (D) or H.P. FORM LII MACT (E) confirming either death or permanent disability, has been caused, as a result of the use of the motor vehicle so insured by such insurance company.

**215-E. Presumption about report.**—The contents of the report sent to the Claims Tribunal in Part-I of H.P. FORM MACT (D) and H.P. FORM LII MACT (E) by the investigating police officer and the registering authority respectively, concerned and the confirmation given under clause (b) of rule 215-C by the insurance company, shall be presumed to be correct and shall be read in evidence without formal proof till it is proved to the contrary.

**215-F. Police report and action thereon.**—(1) The police report under sub-section (6) of section 158, shall be in H.P. FORM LII MACT (D).

(2) On receipt of report mentioned in sub-rule (1) accompanied by the verification reports of driving license, registration certificate of motor vehicle, insurance, permit etc., the Claims Tribunal shall examine the same and may call for such further information or detail as considered necessary, for proper disposal of the matter in accordance with the provision of sub-section (4) of section 166 of the Act.

(3) The Claims Tribunal after examination of the report shall register the claim case and issue notice for appearance in H.P. FORM LII MACT (H), to all the parties concerned, which would include the victim of the accident, or his legal representative, as the case may be, driver, owner and insurer of the vehicle involved.

(4) On receipt of notice under sub-rule (3) the parties shall put in their presence before the Claim Tribunal and declare claim case, if any, and if so, the police report shall be treated as claim case and be tagged to such claim case preferred independently by the parties.

(5) If the person injured or the legal representative of the person deceased do not appear after notice under sub-rule (4), the Claims Tribunal may presume that the said parties are not interested in pursuing the claims for any compensation and on such presumption it shall close the case.

(6) Unless the police report treated as a claim case stands tagged to independent claim case preferred by the parties themselves, the Claims Tribunal shall call upon the person injured or legal representative of the person deceased, as the case may be, and who have appeared in response to the notice, to give before the claim tribunal statement of facts regarding compensation, if any claimed by them in H.P. FORM LII MACT (A).

(7) If statement of facts about compensation claimed are furnished by the parties in the manner as specified in sub-rule (6), the case shall proceed further in the same manner as if parties have come directly before the Claims Tribunal for compensation.

(8) If the statement for claiming compensation has been given by the party, but subsequently commits default in appearance, in that case the provision of Order IX of the Code of Civil procedure, 1908 (5 of 1908) shall apply:

Provided that in case accident in question involves more than one vehicle and persons connected to all such vehicles make claim for compensation, the police report treated as claim case, shall be presumed to be a claim case preferred by each of them and the absence by any one or more of such parties, shall not prejudice the claim of the party, which continues to appear.”.

**4. Substitution of rule 218.**—In the said rules, for rule 218, the following rule shall be substituted, namely:—

Section 169 and 176
---------------------------

**“218 Notice to parties involved.** – If an application for claim is not dismissed under rule 217, the Claim Tribunal shall send the same to the person against whom the applicant claims relief, with a notice in H.P. FORM LII MACT (I) of the date, to put in their appearance before it and may ask them to file their written statement as per rule 219:

Provided that, if documents produced along with the written statement by the applicant are voluminous, the Claims Tribunal may dispense with the requirement to send copies thereof to the opposite party.”.

**5. Substitution of rule 219.**—In the said rules, for rule 219, the following rule shall be substituted, namely:—

**“219. Appearance and examination of the parties.**-(1) The opposite party, shall, at or before the first hearing, or within such further time as the Claims Tribunal may allow, file a written statement which shall become part of the Claim Tribunal’s record.

(2) The opposite party shall file all the documents in support of facts on which he relies in its defense along with the written statement and shall duly prepare list of documents and shall give a copy thereof to the applicant:

Provided that the Claims Tribunal may not allow the opposite party to rely in support of its defence on any document, not filed along with the written statement, unless it is satisfied that, for certain good or sufficient reasons, it was prevented from filing such document earlier.

(3) If the opposite party contests the claim, the Claims Tribunal, if no written statement has been filed by it, shall proceed to examine him qua the claim and shall reduce the oral statements in writing.

(4) The Claims Tribunal may also require the opposite party to furnish the following information,—

- (a) full particulars of all earlier accidents in which it was involved and in which case the claims have been awarded either wholly or in part; and
- (b) the amount of compensation paid in such earlier accidents, the name and address of the victims and the person to whom the damages have been paid and their relation, if any, with the opposite party.”.

**6. Substitution of rule 220.**—In the said rules, for rule 220, the following rule shall be substituted, namely:—

Section 169 and 176
---------------------------

**“220. Summoning of witness.**- If an application is made by any party to the proceeding for the summoning of witnesses, the Claims Tribunal shall, on payment of the expense involved, if

any, issue summons for the appearance of such witness unless it considers that their appearance is not necessary for a just decision of the case:

Provided that where the Claims Tribunal is of the opinion that, party is unable to bear the expenses to summon witnesses, it may not insist for such payment of the expense and in that case the same shall be borne by the Government:

Provided further that in case where the party succeeds claim in whole or in part, the expenses so incurred by the Government, shall be directed to be paid to the Government.”.

**7. Substitution of rule 222.**— In the said rules, for rule 222, the following rule shall be substituted, namely:—

Section 169 & 176
----------------------

**“222 Local inspection.**—(1) The Claims Tribunal, may, at any time during the course of any proceedings before it, visit the site, at which such accident has occurred for the purpose of making a local inspection or examination of any person, who gives information relevant to the claims.

(2) Any party to a proceeding or a representative of any such party, may accompany the Claims Tribunal, for a local inspection.

(3) The Claims Tribunal, after making a local inspection, shall note briefly in a memorandum the facts observed and such memorandum shall form part of the record of the proceedings.

(4) The memorandum under sub-rule (3), may be shown to any party to the proceedings who desires to see it, and a copy thereof may, be supplied to any such party on application, at the rate of rupees two per page.

(5) The claims Tribunal, may if any journey is undertaken under this rule at the instance of a party, require the party, to deposit an amount equivalent to the actual expenses likely to be incurred by it and its staff before hand and it shall draw only the amount so deposited by the parties, to meet all the incidental expenditure in connection with such journey.”.

**8. Insertion of rules 225-A and 225-B.**—In the said rules, after rule 225, the following rules shall be inserted, namely:—

Section 169 & 176
-------------------------

**“225-A. Obtaining of supplementary information and documents.**—The Claims Tribunal shall, obtain whatever supplementary information and documents, which are found necessary, from the police, medical and other authorities and proceed to adjudicate upon the claim, whether the parties who were given notice appear or not, on the appointed date.

**225-B. Power to direct medical examination.**—The Claims Tribunal may, if it considers necessary, direct in H.P. FORM LII MACT (J), any medical officer or any board of medical officers in a Government or municipal hospital, to examine the injured and issue certificate indicating the degree and extent of the disability, if any, suffered as a result of the accident, and it

shall be the duty of such medical officer or board to submit the report within fifteen days of receipt of such direction.”.

**9. Substitution of rule 229.**—In the said rules, for rule 229, the following rule shall be substituted, namely:—

Section 169 & 176
-------------------------

**“229. Determination of issues.**—(1) After framing the issues, the Claims Tribunal shall, proceed to decide such issues after allowing both parties to cross examine each other in accordance with the provision of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(2) The Claims Tribunal may, if it appears to it to be necessary for just decision of the case, allow the parties to adduce such further evidence as it may deem fit:

Provided that no such further opportunity shall be permitted unless it is shown that such further evidence could not be adduced earlier despite exercise of due diligence by or that such evidence was not within the knowledge of the party relying on it.”.

**10. Substitution of rule 231.**—In the said rules, for rule 231, the following rules shall be substituted, namely:—

Section 169 & 176
-------------------------

**“231. Judgment and award of compensation.**—(1) The Claims Tribunal while passing order, shall record concisely in a judgment, the findings on each of the issues framed, the reasons for such findings, and make an award specifying the amount of compensation, to be paid by the insurer or person upon whom the liability has been fastened and also the person, to whom compensation, to be paid by the insurer and also the person, to whom compensation shall be paid. As far as practicable the disbursal of the awarded amount shall be made through electronic transfer (RTGS or NEFT) directly in the account of the beneficiary.

(2) Where compensation is awarded to two or more person, the Claims Tribunal shall also specify the amount payable to each of them.

(3) The procedure of adjudicating the liability and award of compensation may be set apart from the procedure of disbursement of compensation to the legal heirs in a case of death, and where the Claims Tribunal feels that the actual payment to the claimant is likely to take some time because of the identification and determination of legal heirs of the deceased, the Claims Tribunal may call for the amount of compensation awarded to be deposited with it, and, then, proceed with the identification of the legal heirs, for disbursing payment of compensation to each of the legal heirs equitably.

(4) The claims Tribunal shall, obtain a receipt from the claimant in duplicate out of which, one copy shall be issued to the person, who makes the payment, and the other copy to be retained on the record”.

**11. Insertion of rule 231-A.**—In the said rules, after rule 231, the following rule shall be inserted, namely:—

Section 169
----------------

**“231- A. Securing the interest of claimants.**—(1) Where any lump sum amount deposited with the Claims Tribunal, is payable to a person under legal disability, such sum may be invested, applied or otherwise dealt with for the benefit of such person, during his disability, in such manner as the Claims Tribunal may direct, to be paid to any dependent of the injured or heirs of the deceased or to any other person, whom the Claims Tribunal thinks best fit to provide for the welfare of the injured or the heir of the deceased, as the case may be.

(2) Where on application made to the Claims Tribunal in this behalf or otherwise, the Claims Tribunal is satisfied that on account of neglect of the children by their parents or on account of change of circumstances of any dependent or for any other sufficient cause, an order of the Claims Tribunal as to the distribution of any sum paid as compensation or as to the manner in which any sum payable to any such dependent is to be invested or applied or otherwise dealt with, ought to be varied, the Claims Tribunal may make such further orders for the variation of the former order, as it may think just in the circumstances of the case.

(3) The Claims Tribunal shall, in the case of a minor, order that amount of compensation awarded to such minor be invested in fixed deposits till such minor attains majority. The expenses incurred by the guardian or the next friend, may be allowed to be withdrawn by such guardian or such next friend, from such deposits, before the same are deposited.

(4) The claims Tribunal shall, in the case of illiterate claimants, order that the amount of compensation awarded, be invested in fixed deposits for a minimum period of three years, but if any amount is required for effecting purchase of any moveable or immoveable property for improving the income of the claimant, the Claims Tribunal may consider such a request after being satisfied that the amount would be actually spent for the purpose.

(5) The claims Tribunal shall, in the case of semi-literate person, opt the procedure for the deposit of award amounts given in sub-rule (4) unless it is satisfied, for reasons to be recorded in writing that the whole or part of the amount is required for the expansion of any existing business or for the purchase of some property as specified in sub-rule (4) in which case the Claims Tribunal shall ensure that the amount has been invested of the purpose, for which it was prayed for.

(6) The Claims Tribunal may in the case of literate persons may also opt the procedure for deposit of the awarded amount specified in sub-rule (4) and (5), if the age, financial background etc. of the claimant, with a view to ensuring the safety of the compensation awarded, think it necessary and pass such order as it may deem fit.

(7) The Claims Tribunal, may in personal injury cases, if further treatment is necessary, pass an order in writing, permitting to draw such amount, as is necessary for meeting the expenses of such treatment.

(8) The Claims Tribunal shall, in the matter of investment of money, with a view to have maximum return for the claimant, pass orders to deposit the same with public sector undertakings of the State or Central Government, which offers higher rate of interest.

(9) The Claims Tribunal shall, in investing such money, direct that the interest on the deposits be paid directly to the claimants or the guardian of the minor claimants by such institutions under intimation to the Claims Tribunal.”.

**12. Substitution of rule 233.**—In the said rules, for rule 233, the following rule shall be substituted namely:—

**“233. Form and manner of appeals against the award of Claims Tribunal.—**(1) An appeal against the judgment of the Claims Tribunal shall be preferred in the form of a memorandum signed by the applicant or by an advocate duly empowered by such applicant in this behalf, before the High Court and shall be accompanied by a copy of the award.

(2) The memorandum shall concisely specify the grounds of appeal without any argument or narration and such grounds shall be numbered consecutively.

(3) Save as provided in sub-rules (1) and (2), the provisions of Order XLI and XXI in the First Schedule to the Code of Civil procedure, 1908 (5 of 1908) shall *mutatis mutandis* apply to the appeals referred above.”.

**13. Substitution of rule 234.—**In the said rules, for rule 234, the following rule shall be substituted, namely:—

Section 176
----------------

**“234. Fees.—**(1) No court fee shall be leviable on an application under section 166 for payment of compensation.

(2) An amount of the court fee to be charged for inspecting the files shall be twenty rupees for first hour and ten rupees for every subsequent hour in each case.

(3) The carbon copies of the evidence shall be given to the parties concerned, if asked for, on payment of court fee of rupees two per page and application for obtaining such copies shall bear court fee of rupees ten.

(4) An amount of rupees two per page shall be charged in the form of court fee, for obtaining an attested copy of the award on final order or an intermediate order or any documents filed with the Claims Tribunal.”.

**14. Insertion of rule 235-A.—**In the said rules, after rule 235, the following rule shall be inserted, namely:—

Section 176
----------------

**“235-A Custody and preservation of records, Registers and Certified Copies.—**(1) The necessary documents and records relating to the cases, shall be preserved in the record room for a period of six years of the satisfaction of the award, if any, granted or for a period of twelve years after the judgment and award become final, whichever is earlier.

(2) The Claims Tribunal, shall maintain in addition to all registers required to be maintained by the court of an Additional District and Sessions Judge, the following register, namely:—

- (i) register for applications for interim award on principle of no fault liability; and
- (ii) register for deposit of payments in the tribunal through cheques.

(3) Claim petitions on the ground of death, permanent disability, injury and damage to property shall be entered in a separate register.

(4) The rules relating to the issue of a certified copy, followed by the courts subordinate to the High Court, shall *mutatis mutandis* apply to the Claims Tribunal.”.

15. In the said rules, for H.P. FORM LII MACT.A, the following forms shall be substituted, namely:—

**H.P. MACT( A)**  
**[See rules 215 and 215-F (6)]**  
**APPLICATION FOR COMPENSATION BEFORE THE MOTOR**  
**ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL**

To

The Motor Accidents Claims Tribunal,

Photograph of  
claimant(s)

Sir,

I, \_\_\_\_\_ son/daughter/wife/widow of \_\_\_\_\_ residing at \_\_\_\_\_ having been injured in motor vehicle accident hereby apply for the grant of compensation for the injury sustained. Necessary particulars in respect of the injury, vehicle, etc. are given below:—

I/We \_\_\_\_\_ father/mother/son (s)/ daughter (s)/ widow of \_\_\_\_\_ residing at \_\_\_\_\_ hereby apply as legal representative (s) for the grant of compensation on account of death of Shri/Shrimati/Kumari \_\_\_\_\_/injury sustained by Shri/ Shrimati/Kumari \_\_\_\_\_, who died/injured in a motor vehicle accident. Necessary particulars in respect of the deceased/injured/vehicles, etc., are given below:-

1. Name and father's name of the person injured/died (Husband's name in the case of married woman and widow) \_\_\_\_\_
2. Full address of the person injured/died \_\_\_\_\_
3. Age of the person injured/ died \_\_\_\_\_
4. Occupation of the person injured/died \_\_\_\_\_
5. Name and address of the employer of the deceased, if any, \_\_\_\_\_
6. Monthly income of the person injured/died \_\_\_\_\_
7. Does the person in respect of whom compensation is claimed pay income tax? If so, state the amount of the income tax (to be supported by documentary evidence) \_\_\_\_\_
8. Place, date and time of the accident \_\_\_\_\_
9. Name and address of police station in whose jurisdiction the accident took place or was registered \_\_\_\_\_



10. Was the person in respect of whom compensation is claimed traveling by the motor vehicle involved in the accident? If so, give the name and place of starting of journey and destination\_\_\_\_\_
11. Nature of injuries sustained and disablement, if any, caused\_\_\_\_\_
12. Name and address of the Medical officer/ Practitioner, if any, who attended on the injured/ died\_\_\_\_\_
13. Period of treatment and expenditure, if any, incurred thereon (to be supported by documentary evidence)\_\_\_\_\_
14. Registration No. and the type of the motor vehicle involved in accident\_\_\_\_\_
15. Name and address of the insurer of the motor vehicle\_\_\_\_\_
16. Name and address of the owner of the motor vehicle\_\_\_\_\_
17. Has any claim been lodged with the owner/insurer? If so, with what result\_\_\_\_\_
18. Name and address of the applicant \_\_\_\_\_
19. Relationship with the deceased/injured \_\_\_\_\_
20. Title to the property of the deceased/injured \_\_\_\_\_
21. Amount of compensation claimed and basis thereof\_\_\_\_\_
22. Whether report in prescribed form has been obtained from the police and registering \_\_\_\_\_ authorities?\_\_\_\_\_ (if \_\_\_\_\_ so \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_ be annexed)\_\_\_\_\_
23. Whether documents mentioned in rule 215 are being annexed duly Indexed (give details) \_\_\_\_\_
24. Any other information that may be necessary/helpful in the disposal of the claim\_\_\_\_\_
25. Reasons or grounds for the late submission of the claim application on which condonation\_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_ delay \_\_\_\_\_ is claimed \_\_\_\_\_
26. Cause of accident with brief descripti\_\_\_\_\_

Signature or thumb-impression of the applicant(s)

**VERIFICATION**

Verified at \_\_\_\_\_ this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ that the contents of the above application are true and correct to my/own knowledge and belief.

Signature or thumb-impression of the applicant(s)

*Note:—*(1) Applicant shall furnish spare copies of the application equal to the number of respondents, cited in the claim application for sending the same with notices to the respondents.

(2) The application is to be filed within six months of the occurrence of the accident and reasons be given for late submission of the application.

(3) The applicants may send their applications through registered A.D to the Motor Accidents Claims Tribunal.”.

**16. Insertion of HP Forms FORM L II MACT(B) to HP FORM LII MACT(J).—**In the said rules, after FORM H.P. FORM LII MACT (A), the following forms shall be inserted, namely:—

\_\_\_\_\_

**H.P.MACT (B)**

[See rules 215 and 215-A (d)]

**ORDER TO INVESTIGATING POLICE OFFICER****BEFORE THE MOTOR ACCIDENTS CLAIMS TRIBUNAL, HIMACHAL PARDESH**

Case No: \_\_\_\_\_

Title \_\_\_\_\_ Vs. \_\_\_\_\_

Subject: F.I.R No. \_\_\_\_\_

To

Station House Officer,

P.S \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ORDER**

Whereas the claim petition above mentioned seeking payment of compensation has been preferred in this Claims Tribunal in connection with the accident which is stated to be subject matter of investigation by you through FIR particulars stated above;

And whereas the law enjoins upon you to make available to the parties concerned under the provision of section 160 of the Motor Vehicles Act, 1988 and to this Tribunal under the provisions of sub – section (6) of section 158 of the said Act read with rule 150 of the Central Motor Vehicles

Rules, 1989 and rule 215-A of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, document in the nature of.—

- (1) Identification marks and other particulars of the vehicle, which caused the accident;
- (2) Name and address of the person, who was driving/using the same at the time of accident;
- (3) Name and address of the person, who was injured or description of property damaged;
- (4) Copy of the FIR;
- (5) Report under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 along with documents annexed thereto viz., report/postmortem report, mechanical inspection report, photograph taken, site plan prepared, driving license, registration certificate, permit, insurance policy, verification if any, etc; and
- (6) Any other relevant document seized.

Now, therefore, you are hereby directed to send to this claims Tribunal, information in FORM H.P.MACT (D), with clear legible photocopies of all the aforesaid documents duly attested under your personal signatures and bearing your official seal within fifteen days of the receipts of this communication.

Given under my hand and Seal, this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_

MACT

**H.P. FORM LII MACT (C)**  
[See rules 215-A (e) and 215-D (a)]

**APPLICATION TO INVESTIGATING POLICE OFFICER**

Case No: \_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_ Vs. \_\_\_\_\_

Subject: F.I.R. No. \_\_\_\_\_

To

Station House Officer,  
P.S. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Sir,

Whereas the applicant is a party being the claimant/insurance company, in the claim petition above mentioned seeking payment of compensation in connection with the accident which

is stated to be the subject matter of investigation in the FIR particulars of which have been given above,

And whereas, the law enjoins upon you to make available to the parties concerned under the provisions of section 160 of the Motor Vehicles Act, 1988 read with rule 150 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and rule 215A of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Rules, 1999 documents in the nature of—

- (1) Identification marks and other particulars of the vehicle, which caused the accident;
- (2) Name and address of the person, who was driving/using the same at the time of accident;
- (3) Name and address of the person, who was injured, or description of property damaged;
- (4) Copy of the FIR;
- (5) Report under section 173 of the code of criminal Procedure, 1973 with documents annexed thereto viz., report/postmortem report, mechanical inspection report, photograph taken, site plan prepared, driving license, registration certificate, permit, insurance policy, verification, if any, etc: and
- (6) Any other relevant document seized

The undersigned, therefore, requests that the requisite information in FORM H.P.MACT (D) may kindly be furnished to him within fifteen days of the receipt of this communication.

Yours faithfully  
( )

Dated:

Fill name and address

\_\_\_\_\_  
**H.P. FORM LII MACT (D)**  
**(See rule 215-B)**  
**ACCIDENT INFORMATION REPORT**  
**PART-I**

1. FIR No. date of FIR and Sections Charged \_\_\_\_\_
2. Name of the Police station \_\_\_\_\_
3. Date, time and place of accident \_\_\_\_\_
4. Name, father's name and address  
of the person injured/dead \_\_\_\_\_  
(Husband's name in the case of  
Married woman and widow) \_\_\_\_\_
5. Name and address of the driver  
of the offending vehicle(s) \_\_\_\_\_

6. Particulars of driving license of the Driver of offending vehicle(s)\_\_\_\_\_
  - a. Driving license No \_\_\_\_\_
  - b. Period of validity of the license \_\_\_\_\_
  - c. Issuing Authority \_\_\_\_\_
7. Name and address of the owner of the offending vehicle (s):  
\_\_\_\_\_
8. Particulars of the offending vehicles(s):
  - a. Registration No and type of vehicles(s)  
Involved in the accident: \_\_\_\_\_
  - b. Engine No \_\_\_\_\_
  - c. Chassis No. \_\_\_\_\_
  - d. Particulars of permit and fitness  
in case of commercial vehicle \_\_\_\_\_
9. Particulars of the Insurance of the offending vehicle(s):
  - (a) Policy/Cover Note No. \_\_\_\_\_
  - (b) Period of validity of the policy \_\_\_\_\_
  - (c) Name and address of the Insurance Company \_\_\_\_\_
10. Age of the person injured/dead \_\_\_\_\_
11. Occupation of the person injured/dead \_\_\_\_\_
12. Monthly Income of the person injured/dead \_\_\_\_\_
13. Does the person in respect of whom Compensation is claimed pay income Tax? If so, state the amount of the Income Tax. \_\_\_\_\_
14. In case of death, name, age, address and Relationship of the legal representatives of the deceased \_\_\_\_\_
15. In case of injury, nature of injuries sustained, treatment taken and disablement, if any, \_\_\_\_\_
16. Name and address of the Medical Officer/ Practitioner, who attended on the injuries: \_\_\_\_\_
17. Any other additional information \_\_\_\_\_

---

**PART-II****DOCUMENTS TO BE ATTACHED TO THE ACCIDENT  
INFORMATION REPORT**

1. Report under section 176 Cr. P.C.
2. FIR
3. MLC
4. Photography
5. Site Plan
6. Mechanical Inspection report
7. Seizure memos

**In case of Death :**

8. Proof of age of the deceased which may be in form of :
  - (i) Birth certificate.
  - (ii) Matriculation Certificate.
  - (iii) Certificate from gram panchayat (in case of illiterate).
  - (iv) Photo ID card of the deceased.
9. Death certificate and post mortem report of deceased
10. Proof of income of the deceased which may be in form of :
  - (i) Pay Slip/salary certificate for salaried employees.
  - (ii) Bank statements of the last six months.
  - (iii) Income Tax Returns.
  - (iv) Balance Sheets.
11. Proof of the legal representatives of the deceased
  - (i) Names
  - (ii) Age
  - (iii) Address
  - (iv) Relationship
12. Treatment record, medical bills and other expenditure.

**In case of Injury**

13. Proof of age of the injured which may be in the form of :
  - (i) Birth Certificate
  - (ii) Matriculation Certificate
  - (iii) Certificate from Gram Panchayat (in case of illiterate)
  - (iv) Photo- ID card of the injured.
14. Proof of Income of the injured at the time of the accident which may be in form of
  - (i) Pay Slip/ salary certificate for salaried employees
  - (ii) Bank statements of the last six months of the injured
  - (iii) Income Tax Returns
  - (iv) Balance Sheet
15. MLC
16. Treatment record, medical bills and other expenditure- the SHO/IO shall also record the details (in case of long term treatment) so that the claimant may furnish such bills before the Claims Tribunal.
17. Disability certificate
18. Proof of absence from work where loss of income on account of injury is being claimed, which may be in the form of:
  - (i) Certificate from the employer
  - (ii) Extracts from the attendance register
19. Report regarding confirmation of genuineness of the above documents.

(Station House Officer)

**Verification**

Verified at \_\_\_\_\_ on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ that the contents of the above Report are true and correct to my  
 knowledge and belief and the documents mentioned in Part II are verified to be correct.

(Station House Officer)

\_\_\_\_\_

**H.P. FORM LII MACT (E)**  
**[See rules 215-C (a) and (b), 215 – D (c) and (d), 215- E]**  
**REPORT OF THE REGISTERING AUTHORITY**

Case No: \_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_ Vs. \_\_\_\_\_

**To**Motor Accidents Claims Tribunal,  
  
\_\_\_\_\_

Sir,

This is with reference to the order/application dated \_\_\_\_\_ in the above mentioned case. The requisite information is given below:-

## 1. Particulars of the vehicle:

- (a) Registration No:
- (b) Type of Vehicle:
- (c) Make and model:
- (d) Engine No:
- (e) Chassis No:
- (f) Full name and address of the registered owner of the vehicle.

## 2. Particulars of driving license:

- (a) Driving License No. and date of issue /expiry holder:
- (b) Name and address of license holder:
- (c) Particulars of issuing Authority:
- (d) Badge No. in case of public service vehicle:
- (e) Detailed report, if the particulars mentioned are found not genuine:

## 3. Particulars of route permit:

- (a) Permit No. and date of expiry:
- (b) Name and address of permit holder:
- (c) Type of permit.

(Registering Authority)

Verified that the contents of above report are correct as per records of this office.

Date:

(Registering Authority)



**H.P. FORM LII MACT (F)**  
**[See rule 215-C (a)]**

**ORDER TO REGISTERING AUTHORITY**

**BEFORE THE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL HIMACHAL PRADESH**

Case No: \_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_ Vs. \_\_\_\_\_

*Subject:—* (1) Verification of Registration Certificate of vehicle

No. \_\_\_\_\_ and Driving License No. \_\_\_\_\_ in Respect  
 of \_\_\_\_\_ valid up to \_\_\_\_\_ issue by  
 the \_\_\_\_\_ Licensing Authority.

To

Registering Authority  
 \_\_\_\_\_

**ORDER**

Whereas the claim petition mentioned above seeking payment of compensation has been preferred in this Claims Tribunal in connection with an accident allegedly involving motor vehicle, particulars of which are captioned above;

And whereas the vehicle is stated to have been registered by office under your control, and the driving license/permit aforesaid is stated to have been issued by office under your control; And whereas the records relating to the said registration/driving license/permit are required to be maintained by said officer under your control under the Central Motor Vehicle Rules, 1989;

And whereas requisite information relating to the said document is required by this Claims Tribunal for the purposes of inquiry under the provisions of section 168 of the Motor Vehicle Act, 1988, which you are bound to furnish in terms of rule 149 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 read with rule 215-B of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999;

Now, therefore, you are hereby directed to furnish to this Claims Tribunal, the full information regarding registration certificate/driving license/permit aforesaid, with copies of documents in support duly attested by an authorized official and bearing official seal within fifteen days of the receipt of this communication.

Given under my hand and seal, this \_\_\_\_\_ day  
 of \_\_\_\_\_.

MACT

\_\_\_\_\_  
**H.P. FROM LII MACT (G)**  
**[See rule 215-C(b) and 215-D (c)]**  
**APPLICATION TO REGISTERING AUTHORITY**

Case No.: \_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_ Vs. \_\_\_\_\_

To

The Registering Authority,  
\_\_\_\_\_*Subject:*— Vehicle No. \_\_\_\_\_ Permit No. \_\_\_\_\_ Driving  
License No. \_\_\_\_\_ in respect of \_\_\_\_\_

Whereas the undersigned has been impleaded as a party in the claim petition mentioned above seeking payment of compensation in connection with an accident involving Motor Vehicle, particulars of which are captioned above;

And whereas the vehicle aforesaid is stated to have been registered by office under your control, the driving license/permit aforesaid is stated to have been issued by office under your control (Strike out whichever is not applicable);

And whereas the records relating to the said registration driving license/permit are required to be maintained by your office under the Central Motor Vehicles Rules 1989;

And whereas requisite information relating to the documents aforesaid are required by this Claims Tribunal for the purposes of inquiry under the provisions of section 168 of the Motor Vehicles Act, 1988, which you are bound to furnish in terms of rule 149 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 read with rule 215-B of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999;

Now, therefore, the undersigned, requests that complete information regarding registration certificate/driving license/permit aforesaid, with copies of documents in support duly attested under your personal signatures and bearing your official seal may be furnished within fifteen days of the receipt of this application.

(Applicant)

(Full name, particulars and address to be given)

\_\_\_\_\_

**H.P. FORM LII MACT (H)****[See rule 215-F (3)]****NOTICE FOR APPEARANCE TO THE PARTIES****BEFORE THE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL HIMACHAL PRADESH**

Case No. \_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_ Vs. \_\_\_\_\_

**NOTICE**

*In Re:* Police Report under section 158(6) of the Motor Vehicles Act, 1988 treated as Claim case under section 166(4) of the Motor Vehicles Act, 1988

Reference FIR No. \_\_\_\_\_ of P.S. \_\_\_\_\_

To

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Name, Description and Place of residence)

Whereas a report under section 158(6) of the Motor Vehicles Act, 1988, has been received from Station House Officer of the said Police Station with reference to FIR regarding an accident involving use of a motor vehicle;

And whereas the aforesaid report has been treated by this Claims Tribunal, as a claim case in accordance with the provisions of section 166(4) of the Motor Vehicles Act, 1988, in which it appears necessary to call upon you to appear before the undersigned for further proceedings in the matter at \_\_\_\_\_ AM/PM on \_\_\_\_\_ (date);

Now, therefore, you are hereby asked to appear before this Claims Tribunal in person or through a pleader duly instructed and able to answer all material questions relating to the claim case aforesaid on aforesaid date and time;

And as the date fixed for your appearance is appointed for hearing of the claim case and you are required to file on or before the date, an undertaking disclosing full particulars of the claim case, which may have either been preferred or being preferred in respect of the same cause of action by or against you.

Take notice that in default of your appearance on the date and time aforementioned, the claim case will be heard and determined in your absence. Given under my hand and seal of this Tribunal on this \_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_.

MACT

\_\_\_\_\_

**H.P. FORM LII MACT (I)**

(See rule 218)

**NOTICE TO OPPOSITE PARTY****BEFORE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL HIMACHAL PRADESH**

CASE No : \_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_ Vs. \_\_\_\_\_

**NOTICE**

To

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Name, Description and Place of Resident)

Whereas \_\_\_\_\_ has instituted a Motor Accident Claim case impleading you as Respondent \_\_\_\_\_ (Copies of application along with documents filed enclosed), which case has been directed to be listed before this Claim Tribunal, for hearing at \_\_\_\_\_ AM/PM on \_\_\_\_\_ (date)

Now, therefore, you are hereby asked to appear before this Claims Tribunal in person or through a pleader duly instructed and able to answer all material questions relating to the claim case on aforesaid date and time.

And as the date fixed for your appearance is appointed for hearing of the claim case, you may, therefore file on or before that date, a written statement during with the claim raised in the application, along with all the documents in support of all facts on which you rely in your defense on the application, duly entered in the list of documents, where after it shall not be permissible to rely on any further documents, except as provided in rule 219 of Himachal Pradesh Motor Vehicle Rules 1989.

Take notice that in default of your appearance on the date aforementioned, the claim case will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and seal of this Tribunal on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_

MACT.

### H.P. FORM LII MACT (J)

(See rule 225-B)

### DIRECTION FOR MEDICAL EXAMINATION BEFORE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL HIMACHAL PRADESH

CASE No : \_\_\_\_\_

Title : \_\_\_\_\_ V/s. \_\_\_\_\_

To \_\_\_\_\_

Photograph of  
claimant(s)

### ORDER

Whereas the aforesaid claim petition seeking payment of compensation has been preferred in this Claims Tribunal in connection with an accident involving use of motor vehicle and the claimant \_\_\_\_\_

s/o, d/o, w/o \_\_\_\_\_

aged \_\_\_\_\_ r/o \_\_\_\_\_ whose

photograph bearing his specimen signature/ thumb impression is affixed above, is alleged to have suffered injuries as a result of the said accident, which are stated to have been recorded in medico

Legal Certificate No. \_\_\_\_\_

dated \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ (name of hospital);

And whereas for the purpose of inquiry into the claim petition, this Claims Tribunal considers it necessary to ascertain the degree and extent of disability, if any, suffered as a result of the said accident by the said claimant;

Now, therefore, in exercise of powers vesting in this Claims Tribunal, in terms of rule of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, the undersigned directs you to get the said claimant examined by a Medical Officer/ Board of Medical Officers in your Hospital and submit report on above aspects to this Claims Tribunal within a period of fifteen days of the receipt of this direction.

Given under my name and seal of this Tribunal, this \_\_\_\_\_  
day of \_\_\_\_\_.”

M.A.C.T

By order,  
Sd/-

*Addl. Chief Secretary (Transport).*

**ELECTION DEPARTMENT**  
**Block No.38, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009**

NOTIFICATION

*Dated, the 5th October, 2021*

**No. 5-11/2018-ELN.**—On the recommendations of Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order, promotion of Sh. Mohinder Thakur, Naib-Tehsildar (Election), District Election Office, Solan to the post of Tehsildar (Election), Class-I (Gazetted) in the pay scale of Rs. 10300—34800/- plus Rs. 5000/- Grade Pay and posting in the District Election Office, Lahaul & Spiti at Keylong against vacancy of Tehsildar (Election), with immediate effect.

The above officer will remain on probation for a period of two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

The above officer will have to exercise option for fixation of pay under the provisions of saving clause of FR-22(I)(a)(1) within a period of one month from the date of joining as Tehsildar (Election).

The above promotion shall be subject to the final decision of the CWP No. 2784/2019 filed before the Hon'ble H.P. High Court, Shimla. Keeping in view the bye-elections to 2-Mandi Parliamentary Constituency, the aforesaid officer will join as Tehsildar (Election) in District Election Office, Lahaul & Spiti at Keylong within one week from the date of issuance of this promotion order.

By order,  
C. PAULRASU, IAS,  
*Chief Electoral Officer-cum-Secretary (Election).*

**न्यायालय श्री पूर्ण चन्द कौंडल, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब-तहसीलदार,  
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0**

श्री सुनील आर्य पुत्र सन्तराम आर्य, वासी टीका धुलेडा, मौजा बमसन, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

यह दरखास्त श्री सुनील आर्य पुत्र सन्तराम आर्य, वासी टीका धुलेडा, मौजा बमसन, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड में सुनील आर्य दर्ज है जो कि सही है। परन्तु पटवार वृत्त टिक्कर खतरियां के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम सुनील कुमार दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 14-10-2021 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 18-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,  
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

**न्यायालय श्री पूर्ण चन्द कौंडल, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब-तहसीलदार,  
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0**

श्री सुनील आर्य पुत्र सन्तराम आर्य, वासी टीका धुलेडा, मौजा बमसन, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

यह दरखास्त श्री सुनील आर्य पुत्र सन्तराम आर्य, वासी टीका धुलेडा, मौजा बमसन, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसके पिता का नाम पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड में सन्तराम आर्य दर्ज है जो कि सही है। परन्तु पटवार वृत्त टिक्कर खतरियां के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम सन्तू दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 14-10-2021 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल धुलेडा में सन्तराम आर्य के स्थान पर सन्नू उपनाम सन्तराम आर्य दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद में कोई भी उजर व एतराज काबीले समायत ना होगा।

आज दिनांक 15-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी,  
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)**

श्रीमती सपना भाग सिंह पुत्री भाग सिंह, वासी टीका स्वाहलवा, डाकघर टौणी देवी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2019-23479, दिनांक 19-08-2021 के अनुसार श्रीमती सपना भाग सिंह पुत्री भाग सिंह, वासी टीका स्वाहलवा, डाकघर टौणी देवी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 05-10-1976 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत नाडसी के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 05-10-1976 को दर्ज न हो सका तथा अब प्रार्थिया जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत नाडसी में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सपना भाग सिंह पुत्री भाग सिंह, वासी टीका स्वाहलवा, डाकघर टौणी देवी, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) की जन्म तिथि 05-10-1976 को ग्राम पंचायत नाडसी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2021 तक असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 06-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

**In the Court of Shilpi Beakta, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Ashok Rawat aged 29 years s/o Sh. Anand singh Rawat, r/o 488/1-A, Old No. 12G/F, Dalshad Garden, Jhilmil Eat Delhi-110095.
2. Reetu Kumar aged 29 years d/o Shri Madan Lal, Village Chamyola, P. O. Chauri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

*Versus*

General Public

*Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).*

Ashok Rawat aged 29 years s/o Sh. Anand simgh Rawat, r/o 488/1-A, Old No. 12G/F, Dalshad Garden, Jhilmil Eat Delhi-110095 and Reetu Kumar aged 29 years d/o Shri Madan Lal, Village Chamyola, P. O. Chauri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 07-12-2020 at Village Chamyola, P. O. Chauri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 18-10-2021. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 17-09-2021 under my hand and seal of the court.

Seal.

SHILPI BEAKTA, H.A.S.,  
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

**In the Court of Dr. Charanji Lal, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Sh. Shashi Chauhan s/o Sh. Jagdish Singh, r/o Village & P. O. Jahu, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) at present residing at c/o Sh. Naresh Kumar s/o Late Sh. Om Prakesh r/o Village Sasan, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Ms. Seema Devi d/o Sh. Rameshswar Nath, r/o Village Gulella, P.O. Baldwara, Tehsil & District hamirpur (H.P.)  
.. Applicants.



*Versus*

General Public

Subject.— Notice of Intended Marriage

Sh. Shashi Chauhan & Ms. Seema Devi have filed an application u/s 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they intend to solemnized their marriage within next three calendar months.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 18-10-2021. In case no objection is received by 18-10-2021, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 31-08-2021.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-SDM,  
Hamirpur, District Hamirpur (H.P.).*

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

श्री कमरवीर पाल सुपुत्र श्री प्रभात सिंह, गांव कोटली, डाकघर बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय : राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे आवेदन-पत्र।

श्री कमरवीर पाल सुपुत्र श्री प्रभात सिंह, गांव कोटली, डाकघर बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत बीड़ व अन्य दस्तावेजों में कमरवीर पाल दर्ज है जो उसका सही नाम है। परन्तु रिकार्ड में गलती से कर्मवीर पाल ही दर्ज हुआ है। अब राजस्व रिकार्ड में कमरवीर पाल दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को दुरुस्त करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 08-10-2021 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 09-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

श्रीमती संतोषी देवी पत्नी श्री सीता राम, निवासी बीड़, डाकघर बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती संतोषी देवी पत्नी श्री सीता राम, निवासी बीड़, डाकघर बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र तनिष्क ठाकुर का जन्म दिनांक 30-12-2006 को महाल बीड़ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 14-10-2021 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असातन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है, अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 13-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

श्री राकेश सिंह पुत्र ओम प्रकाश, निवासी महाल वैही घमलेहड, डाकघर जम्बल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र दुरुस्ती नाम कागजात माल महाल वैही घमलेहड, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

श्री राकेश सिंह पुत्र ओम प्रकाश, निवासी महाल वैही घमलेहड, डाकघर जम्बल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना—पत्र दिया है कि उसका सही नाम पंचायत रिकार्ड, स्कूल रिकार्ड व आधार कार्ड में राकेश सिंह पुत्र ओम प्रकाश है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल वैही घमलेहड में उसका नाम राकेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश पुत्र हंस राज दर्ज है जो सही न है। प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह

दिनांक 14-10-2021 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में नाम दुरुस्त करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 22-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं० 52/NT/2021

Sh. Moti Lal s/o Rattan Chand, r/o Village Upper Barol, Slum Area, P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Sh. Moti Lal s/o Rattan Chand, r/o Village Upper Barol, Slum Area, P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे पुत्र का जन्म दिनांक 03-11-2003 को हुआ है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Mohan Lal s/o Moti Lal के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 14-10-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि 03-11-2003 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 58/NT/2021

Sh. Tenzin Palzom w/o Tashi Topgyal, Upper TCV, Dharamshala Cantt., Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Sh. Tenzin Palzom w/o Tashi Topgyal, Upper TCV, Dharamshala Cantt., Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरे पुत्र का जन्म दिनांक 20-09-2002 को हुआ है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Tenzin Tsewang के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 14-10-2021 को असातन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि 20-09-2002 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला, तहसील धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 /NT/2021

Smt. Rina Mahat d/o Late Sh. Jang Bahadur Thapa and Smt. Krishan Kanta, r/o Ward No. 12, Upper Barol, P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Smt. Rina Mahat d/o Late Sh. Jang Bahadur Thapa and Smt. Krishan Kanta, r/o Ward No. 12, Upper Barol, P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 15-04-1957 को हुआ है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Rina Mahat के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 14-10-2021 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म 15-04-1957 तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-08-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम।

पेशी : 14-10-2021

रविन्द्र कुमार पुत्र श्री रूप सिंह, निवासी महाल व मौजा रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.— महाल रजोल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम रविन्द्र कुमार पुत्र श्री रूप सिंह है। लेकिन राजस्व अभिलेख महाल रजोल में रविन्द्र चन्द पुत्र श्री रूप सिंह दर्ज है जोकि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 14-10-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 04-09-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.)**

1. Sh. Vinod Kumar aged 31 years s/o Shri Amarjit Singh, r/o V.P.O. Tiara, Tehsil & District Kangra (H.P.).

2. Ranju Bala aged 25 years d/o Sh. Kashmir Singh, r/o V.P.O. Sunehar, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).

*Versus*

General Public

Subject.— Notice for Registration of Marriage

Applicants Sh. Vinod Kumar aged 31 years s/o Shri Amarjit Singh, r/o V.P.O. Tiara, Tehsil & District Kangra (H.P.) & Ranju Bala aged 25 years d/o Sh. Kashmir Singh, r/o V.P.O. Sunehar, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.) has filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 26-10-2020 at "Mata Devi Mandir Chamunda, Tehsil Dharamshala" as per Hindu rites and customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, can file the objections personally or in writing before this court on or before 14-10-2021. The objection received after 14-10-2021, will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 13-09-2021 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).*

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 07-10-2021

जनक राज पुत्र करतार सिंह, निवासी डुढम्ब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37(2) के तहत महाल चड़ी डुढम्ब में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम जनक राज पुत्र करतार सिंह है जबकि महाल चड़ी डुढम्ब के राजस्व अभिलेख में उक्त नाम

कुलविन्द्र सिंह पुत्र करतार सिंह दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त महाल में उक्त नाम को कुलविन्द्र सिंह उपनाम जनक राज पुत्र करतार सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 07-10-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

अतः पटवारी हल्का डुढम्ब को निर्देश दिया जाता है कि मामले में मुशत्री मुनादी करवाने उपरांत रिपोर्ट मय रपट रोजनामचा इस कार्यालय को पेशी से पूर्व भेजने की व्यवस्था करें।

आज दिनांक 07-09-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

#### ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 08-10-2021

राजीब कुमार पुत्र किशोरी लाल, निवासी गांव क्यारी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल क्यारी व झुलाड़ में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम राजीब कुमार पुत्र किशोरी लाल है जबकि महाल क्यारी व झुलाड़ के राजस्व अभिलेख में उसका नाम रंजय कुमार पुत्र किशोरी लाल पुत्र साली दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके रंजय कुमार उपनाम राजीब कुमार पुत्र किशोरी लाल पुत्र साली दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 08-10-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 06-04-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्रीमती प्रेम सरीता, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर,  
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश**

श्रीमती निर्मला पुत्री सुभदा देवी हालाबाद पत्नी मोहर सिंह, गांव दलान, डा0 वीरगढ़, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 75/202, महाल निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरखास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थिया श्रीमती निर्मला पुत्री तारा चन्द, गांव दलान, डा0 वीरगढ़, उप-तहसील कोटगढ़, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड, छायाप्रति विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र के मुताबिक प्रार्थिया का नाम निर्मला सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं0 75/202, महाल निरथ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना मालिक में शुटटी पुत्री सुभद्रा देवी दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थिया का सही नाम निर्मला है जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थिया ने छायाप्रति पंचायत रिकार्ड आदि अन्य दस्तावेज संलग्न दरखास्त कर रखे हैं। प्रार्थिया अपना नाम उक्त माल कागजाल में शुटटी के स्थान पर निर्मला दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में निर्मला दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 06-10-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

(प्रेम सरीता),

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्रीमती प्रेम सरीता, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर,  
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश**

श्री सुशील कुमार पुत्र स्व0 श्री बसन्त राम, निवासी गांव बेलू, डा0 सूरड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम



आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं० 62/169 ता 189, महाल कलेडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरखास्त नाम दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री सुशील कुमार पुत्र श्री बसन्त राम, निवासी गांव बेलू, डा० सूरड, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि आधार कार्ड, पंचायत अभिलेख के मुताबिक प्रार्थी के पिता का नाम बसन्त राम पुत्र लच्छमी नन्द सही व दुरुस्त है परन्तु अराजी खाता/खतौनी नं० 62/169 ता 189, महाल कलेडा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०) के खाना मालिक में सन्त राम पुत्र लच्छमी नन्द दर्शाया गया है जोकि गलत है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम बसन्त राम पुत्र लच्छमी नन्द है जिसकी पुष्टि के लिए प्रार्थी ने छायाप्रति आधार कार्ड व पंचायत अभिलेख संलग्न दरखास्त कर रखे हैं। प्रार्थी अपने पिता का नाम उक्त माल कागजाल में सन्त राम पुत्र लच्छमी नन्द के स्थान पर बसन्त राम पुत्र लच्छमी नन्द दुरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में बसन्त राम पुत्र लच्छमी नन्द दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 08-10-2021 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 10-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

(प्रेम सरीता),

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री हरी राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला,  
हिमाचल प्रदेश

श्री बालक राम पुत्र श्री शोविया, गांव शराण, डाकघर सरी, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

विषय.— 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री बालक राम पुत्र श्री शोविया, गांव शराण, डाकघर सरी, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बम्टा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत थुन्दल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	अंशू	पुत्र	08-11-2013

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत थुन्दल को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज तारीख 21-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
(हरी राम),  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।